सच बोलने की हिम्मत

राजधानी चौपाल

RNI No. HARHIN/25/A3341

अंक : 14 | वर्ष : 01 | साप्ताहिक (08 से 14 अप्रैल 2026) | पृष्ठ 8 | मूल्य : 5/- रुपये | E-mail : rajdhanichoupal@gmail.com

राजधानी चौपाल
समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के समाचार, विज्ञप्ति और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें...
94169-26329
93068-13001

माननीयों की 'कंजूसी': बजट का अंबार, फिर भी विकास को तरस रही जनता!

कहीं 44% तो कहीं सिर्फ 3%: हरियाणा के सांसदों की निधि खर्च करने में भारी असमानता, सैलजा और राव इंद्रजीत भी पीछे

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा के सांसदों के कामकाज और उनके संसदीय क्षेत्र विकास निधि (MPLADS) के खर्च को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के अधिकतर सांसद अपनी निधि खर्च करने में 'कंजूसी' दिखा रहे हैं। जहां कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल 44% खर्च के साथ प्रदेश में सबसे आगे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल के सांसद मनोहर लाल मात्र 3% खर्च के साथ सबसे निचले पायदान पर हैं। 22 महीने के कार्यकाल के दौरान सांसदों के पास विकास कार्यों के लिए करोड़ों का बजट उपलब्ध था, लेकिन धरातल पर काम की रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है।

नियमों के अनुसार, प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये की विकास निधि मिलती है। इस लिहाज से पांच साल के कार्यकाल में एक सांसद को कुल 25 करोड़ रुपये मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के सांसदों को उनके दूसरे साल के लिए अब तक 9.80 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है। हालांकि, इस भारी-भरकम बजट के बावजूद कई क्षेत्रों में एक भी नया काम पूरा नहीं हो सका है।

▪ नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : खर्च में सबसे आगे (44%) : नवीन जिंदल प्रदेश के सबसे सक्रिय सांसदों में उभरे हैं। उन्होंने अब तक 7.98 करोड़ रुपये के 196 कार्यों की सिफारिश की, जिनमें से 192 कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है। अब तक 4.35 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 85 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

▪ जय प्रकाश (हिसार) - सिफारिश में नंबर-1 (41%) : हिसार के सांसद जय प्रकाश ने सबसे अधिक 9.72 करोड़ रुपये की लागत के 271 कार्यों की सिफारिश की। इनमें से 4.01 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। हालांकि, सिफारिशों के मुकाबले काम की गति अभी भी मध्यम बनी हुई है।

▪ दीपेंद्र सिंह हुड्डा (रोहतक) - संतुलित प्रदर्शन (39%) : रोहतक के सांसद ने 9.61 करोड़ रुपये के 142 कार्यों की सिफारिश की है। अब तक कुल 3.81 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो उनके प्रदर्शन को संतुलित श्रेणी में रखता है।

▪ राव इंद्रजीत सिंह (गुरुग्राम) - सीमित काम (16%) : केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के क्षेत्र में काम की गति काफी धीमी है। उन्होंने 45 कार्यों की सिफारिश की, जिनमें से केवल 5 कार्य ही पूरे हो पाए हैं। कुल खर्च 1.55 करोड़ रुपये रहा है।

▪ कुमारी सैलजा (सिरसा) - काम ज्यादा, खर्च कम (13%) : कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा ने 7.07 करोड़ रुपये के 207 कार्यों की सिफारिश की, लेकिन खर्च के मामले में वह पिछड़ गईं। अब तक केवल 1.32 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं और 38 काम पूरे हुए हैं।

▪ मनोहर लाल (करनाल) - सबसे सुस्त (3%) : पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा है। उन्होंने 2.68 करोड़ रुपये के 16 कार्यों की सिफारिश की, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ। अब तक फंड से केवल 30 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं।

▪ सतपाल ब्रह्मचारी (सोनीपत) - खर्च ठीक, काम कम (18%) : सोनीपत में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। 8.24 करोड़ रुपये की सिफारिश के बावजूद अब तक मात्र 6 कार्य ही पूरे हो सके हैं। कुल 1.80 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है।

▪ कृष्ण पाल गुर्जर (फरीदाबाद) - सबसे पीछे (7%) : केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 4.06 करोड़ रुपये के 51 कार्यों की सिफारिश की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके क्षेत्र में केवल एक कार्य ही पूरा हुआ है। कुल खर्च मात्र 64 लाख रुपये रहा।

▪ वरुण चौधरी (अंबाला) - सिफारिश ज्यादा, काम कम (16%) : वरुण चौधरी ने 8.06 करोड़ के 101 कार्यों की सिफारिश की, लेकिन केवल 2 काम ही पूरे हो सके।

ईरान बोला- अमेरिका ने सीजफायर की 3 शर्तें तोड़ीं

अब बातचीत बेकार, ट्रम्प बोले- समझौते तक ईरान के आसपास आर्मी तैनात रहेगी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल)| ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर की तीन अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10-पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा है कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी, वही पहले ही टूट चुका है। ऐसे में अब बातचीत या सीजफायर तर्कसंगत नहीं रह गया है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ, तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है।

लेबनान में इजराइली हमलों से एक दिन में 254 मौतें : इजराइली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक, इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1,165 लोग घायल हुए। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हमले बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिण लेबनान के कई गांवों में किए गए। यह हमला उसी दिन हुआ, जब अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर का ऐलान किया गया था। इजराइली सेना ने कहा कि यह हमला 2 मार्च से शुरू किए गए उनके नए सैन्य ऑपरेशन के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सेना के मुताबिक, इसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान अमेरिका-ईरान सीजफायर का हिस्सा नहीं है। वहीं, मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि इस सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि लेबनान इस समझौते से अलग है और इसका हिस्सा नहीं है।

ईरान होर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों पर 1 डॉलर प्रति बैरल टोल लगाया

ईरान होर्मजु स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों से हर बैरल पर 1 डॉलर टैक्स लेने की योजना बना रहा है। ईरान यह भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में चाहता है। यह खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दी है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखेगा और कंट्रोल करेगा। जहाजों को पहले अपने माल (कार्गो) की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत मिलेगी। ईरान के अधिकारी हामिद होसैनी ने कहा कि यह इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक दो हफ्तों में हथियारों की आवाजाही न हो सके। उन्होंने कहा कि जहाजों को जाने दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस में समय लग सकता है क्योंकि ईरान किसी जल्दी में नहीं है।

निजी स्कूलों की 'फीस' वाली मनमानी, 553 स्कूलों पर विभाग की टेढ़ी नजर

हिसार (राजधानी चौपाल) | हरियाणा के शिक्षा जगत में इन दिनों 'फार्म नंबर-6' को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां प्रदेश के अधिकांश निजी स्कूलों ने पारदर्शिता की राह चुनते हुए अपनी फीस का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है, वहीं दूसरी ओर 553 स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने शिक्षा निदेशालय के आदेशों को ठेंगे पर रखा है। पोर्टल बंद होने के बाद अब इन 'डिफॉल्टर' स्कूलों पर गाज गिरनी तय है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वाले स्कूलों को अब नोटिस थमाकर जवाब-तलब किया जाएगा।

प्रदेश के कुल 9230 निजी स्कूलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी हद तक संतोषजनक है। इनमें से 8677 स्कूलों (94.01%) ने समय रहते फार्म नंबर-6 भरकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

जिलों के प्रदर्शन में नूंह-मेवात ने सबको चौंकाते हुए 98.68% के साथ पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, सोनीपत (97.12%) दूसरे और कुरुक्षेत्र (96.97%) तीसरे स्थान पर रहे। अंबाला और फतेहाबाद ने भी क्रमशः चौथे और पांचवें पायदान पर रहते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र रहा करनाल इस मामले में सबसे पीछे यानी फिसड्डी साबित हुआ है, जहां केवल 88.55% स्कूलों ने ही फीस का ब्यौरा दिया।

रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि कई बड़े स्कूलों ने प्राथमिक शिक्षा का ब्यौरा तो दे दिया है, लेकिन नौवीं से बारहवीं कक्षा की फीस बताने में परहेज किया है। विशेष रूप से अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पंचकूला, रोहतक और सोनीपत जिलों के स्कूलों ने नौवीं और दसवीं कक्षा की फीस के कॉलम खाली छोड़ दिए हैं।

अभिभावक संगठनों का मानना है कि स्कूल जानबूझकर इन कक्षाओं की फीस छिपा रहे हैं क्योंकि बोर्ड कक्षाओं के नाम पर वसूल की जाने वाली भारी-भरकम राशि पर विभाग की नजर न पड़े। फार्म नंबर-6 का उद्देश्य ही यही है कि विभाग को यह पता रहे कि स्कूल जमीन पर अभिभावकों से कितनी राशि वसूल रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर कितना खर्च दिखा रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि इस नियम को तोड़ने वालों में शहर के वे चर्चित और पुराने स्कूल शामिल हैं, जहां शहर के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वर्षों से स्थापित होने के बावजूद ये संस्थान शिक्षा निदेशालय के आदेशों की परवाह नहीं कर रहे हैं। इन स्कूलों के पास संसाधनों और प्रबंधकों की कोई कमी नहीं है, फिर भी डेटा छिपाना इनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

चेतावनी: शुरू होगा कार्रवाई का दौर

शिक्षा निदेशालय ने 5 अप्रैल तक फीस बताने की समय सीमा तय की थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी वेद सिंह दहिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि डेटा न देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया जाए। विभाग ने इन सभी 553 स्कूलों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है।

सार्वजनिक उपयोग की जमीनों से छेड़छाड़ पर सख्ती

सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और प्रशासन को मिलेगा सख्त कार्रवाई का अधिकार

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा सरकार ने राज्य में सार्वजनिक उपयोग की जमीन और सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 'हरियाणा लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिबंध अधिनियम 2022' का 2026 में संशोधित प्रारूप जारी करते हुए इसे लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। यह अधिसूचना राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सोमवार को अधिसूचित कर दी गई है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में मौजूद सड़कों, रास्तों, नालों, नहरों, सार्वजनिक भवनों, जल निकासी व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियों को किसी भी तरह की छेड़छाड़, अतिक्रमण या नुकसान से बचाना है।

हरियाणा सरकार के विधि तथा विधायी विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कानून उन सभी सार्वजनिक उपयोगिताओं पर लागू होगा जो निर्धारित तिथि तक कम से कम 20 वर्षों से अस्तित्व में हैं। यानी लंबे समय से आम जनता द्वारा उपयोग में लाई जा रही सुविधाओं को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। कानून के तहत कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सोसाइटी या संस्था किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता में बाधा नहीं डाल सकेगी और न ही उसका स्वरूप बदल सकेगी। ऐसी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुविधा में अवरोध या परिवर्तन करता है, तो संबंधित जिले का कलेक्टर स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकेगा। कलेक्टर दोषी व्यक्ति को सुनवाई का मौका देने के बाद उस सुविधा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश दे सकता है। साथ ही, मरम्मत या बहाली में आने वाला खर्च भी दोषी व्यक्ति से भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर आयुक्त के पास अपील की जा सकती है।

पुडुचेरी में कांग्रेस-भाजपा समर्थक भिड़े

एंटनी बोले- केरल में बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता; हिमंता ने कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद वोट डाला

गुवाहाटी/तिरुवनंतपुरम/पुडुचेरी (राजधानी चौपाल)| देश के तीन राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है। कुल 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक असम में 75.91%, केरलम में 62.71% और पुडुचेरी में 72.40% वोटिंग हुई है। पुडुचेरी में मन्नादिपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे। केरलम में पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस लीडर ए.के. एंटनी ने तिरुवनंतपुरम में वोट डाला। उन्होंने मीडिया से कहा- केरलम के लोग भाजपा को पसंद नहीं करते। राज्य में 10 साल के कुशासन की सरकार है। इसलिए इस बार सरकार बदलेगी।

वहीं, असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा की है। इसके बाद दोपहर में पत्नी के साथ जालुकवारी में वोट डाला। असम में 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केरलम में 2.71 करोड़ वोटर 890 उम्मीदवारों में से अपना नेता चुनेंगे। पुडुचेरी में 20 पार्टियां के 294 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। केरलम में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी हिमंता बिस्व सरमा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है। जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन. रंगास्वामी पांचवी बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। केरलम तिरुवनंतपुरम में एक्टर मोहनलाल ने वोट किया। केरलम भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में वोट किया। वे नेमम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केरलम के सीएम पिनाराई विजयन ने कन्नूर में आरसी अमला बेसिक अपर प्राइमरी स्कूल में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने त्रिशूर में मतदान किया।

गौरव गोगोई बोले- चुनाव के बाद एक शक्तिशाली और नया असम उभरेगा

जोरहाट (असम) में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अपना वोट डाला और कहा कि चुनाव के बाद एक "शक्तिशाली, निडर, आत्मविश्वासी और नया असम" उभरेगा। जोरहाट के डीसीबी एलपी स्कूल में अपनी मां डॉली गोगोई के साथ वोट डालने के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि राज्य में नई सरकार सभी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी।

जनगणना 2027 | हरियाणा में एक मई से होगी शुरुआत

60 हजार कर्मचारी जनगणना करेंगे, प्राइवेट शिक्षक भी लगेंगे, प्रदेश में पूर्व सैनिकों का लेंगे सहयोग

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 60 हजार से अधिक कर्मचारियों की जनगणना में ड्यूटी लगाई गई है। इन सभी को 6 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के अनुसार फील्ड वर्क से पहले प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण अलग-अलग बैचों में सभी जिलों में आयोजित होगा। यह डिजिटल जनगणना होगी, जो पुरानी डेटा संग्रहण प्रणाली को बदल देगी। राज्य में जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत एक मई 2026 से होगी।

जनगणना निदेशक ललित जैन के अनुसार हरियाणा में पहले चरण का कार्य मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना एक से 30 मई तक चलेगा। पहले 34 मास्टर ट्रेनरों ने 888 फील्ड ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया था। कर्मचारियों को तीन दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके 1400 से ज्यादा बैच होंगे। जनगणना में प्राइवेट शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। खुद के मोबाइल से कर्मचारी यह आंकड़ा जुटाएंगे। जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जनगणना करेंगे।

स्व-गणना: खुद दर्ज करें अपनी जानकारी : डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने स्व-गणना पोर्टल की सुविधा दी है। नागरिक HTTPS://SE.CENSUS.GOV.IN पोर्टल पर जाकर 16 से 30 अप्रैल तक अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। जानकारी दर्ज करने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी मिलेगी। जब प्रगणक आपके घर आएगा, तो उसे बस यह आईडी दिखानी होगी। आईडी साझा करते ही आपका डेटा पोर्टल पर सत्यापित होकर दर्ज हो जाएगा।

33 सवाल पूछे जाएंगे, मोबाइल नंबर दर्ज होगा : घर-घर जाकर 33 सवाल पूछे जाएंगे। मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा। मकान की स्थिति से लेकर परिवार के संसाधनों की जानकारी शामिल होगी। मकान का नंबर, दीवार, छत और फर्श की सामग्री, मकान का उपयोग, उसकी स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, पीने के पानी, बिजली और शौचालय, रसोई, गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी।

बिना किसी डर के दें जानकारी... सरकार ने अनुरोध किया कि वे बिना भय या संकोच के सही एवं पूर्ण जानकारी दें। आपकी जानकारी सुरक्षित है। इसका उपयोग केवल नीति निर्माण के लिए किया जाएगा।

कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी : नागरिकों को किसी भी दस्तावेज को दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से नागरिक-अनुकूल और विश्वास पर आधारित है। बिना कागजात की प्रक्रिया है। डेटा संग्रह के दौरान किसी भौतिक दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। यह डेटा अगले एक दशक तक कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का आधार बनेगा। इस बार जनगणना में आधुनिक सुविधाओं को भी शामिल किया गया है, इनमें इंटरनेट की उपलब्धता, मोबाइल/स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर, टीवी, रेडियो जैसे उपकरण शामिल हैं। वाहन जैसे साइकिल, बाइक व कार को शामिल किया जाएगा।

जनगणना के पहले चरण में पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

मकान और उसकी बनावट

1. भवन संख्या (नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकरण का नंबर)।
2. जनगणना मकान नंबर।
3. मकान में इस्तेमाल सामग्री (मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, पत्थर आदि)।
4. दीवार में इस्तेमाल सामग्री (घास, ईंट, पत्थर, कंक्रीट आदि)।
5. छत में इस्तेमाल सामग्री (खपरैल, टिन, लोहे की चादर, कंक्रीट)।
6. जनगणना मकान का उपयोग (आवासीय, दुकान या अन्य)।
7. मकान की हालत (अच्छी, रहने योग्य या जर्जर)।
8. घर का नंबर (परिवार के लिए)।
9. परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या।

परिवार और मुखिया की जानकारी

10. परिवार के मुखिया का नाम।
11. मुखिया पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर।
12. क्या मुखिया अनुसूचित जाति (एससी) से है?
13. क्या मुखिया अनुसूचित जनजाति (एसटी) से है?
14. क्या मुखिया किसी विशेष समुदाय से है? (जाति संबंधी जानकारी)।
15. मकान के मालिकाना हक की स्थिति (अपना या किराए का)।

सुविधाएं और संसाधन

16. परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या।
17. परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या।
18. पीने के पानी का मुख्य स्रोत (नल, हैंडपंप, कुआं आदि)।
19. क्या पानी का स्रोत परिसर के भीतर है या बाहर?
20. प्रकाश (रोशनी) का स्रोत (बिजली, केरोसिन, सौर ऊर्जा आदि)।
21. शौचालय की उपलब्धता और उसका प्रकार।
22. गंदे पानी की निकासी (ड्रेनेज) की व्यवस्था।
23. स्नान (नहाने) की सुविधा की उपलब्धता।
24. रसोई की उपलब्धता और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन।
25. खाना पकाने के लिए ईंधन (गैस, लकड़ी, कोयला आदि)।
26. रेडियो/ट्रांजिस्टर की उपलब्धता।
27. टेलीविज़न की उपलब्धता।

डिजिटल उपकरण और वाहन

28. इंटरनेट की सुविधा (ब्रॉडबैंड/मोबाइल डेटा)।
29. लैपटॉप/कंप्यूटर की उपलब्धता।
30. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन।
31. साइकिल की उपलब्धता।
32. स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड की उपलब्धता।
33. कार/जीप/वैन की उपलब्धता।

बीबीएमबी को लिखे पत्र में हरियाणा ने उठाया पानी की कमी का मुद्दा, पंजाब के साथ बीबीएमबी जल वितरण पर पहले हो चुका घमासान

हरियाणा को ब्यास नदी से नहीं मिल रहा पूरा पानी, बीबीएमबी को लिखा पत्र

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| नदी जल बंटवारे को लेकर हरियाणा ने फिर से प्रदेश में बड़े संकट की आशंका जताई है। पिछले साल बीबीएमबी के जल वितरण को लेकर हरियाणा व पंजाब के बीच कई दिनों तक ठनी रही। अब हरियाणा ने बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) को पत्र लिखकर कहा है कि उसे मौजूदा समय में ब्यास नदी से उसके सही कोटे का पानी नहीं मिल रहा है। राज्य ने ब्यास-सतलुज लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से ब्यास से सतलुज में पानी के कम डायवर्जन को इस परेशानी का मुख्य कारण बताया है।

हरियाणा ने अपने पत्र में कहा है कि चार मार्च से बीएसएल (ब्यास सतलुज लिंक) से पानी कम छोड़ा जा रहा है। इससे भाखड़ा सिस्टम के जरिए हरियाणा को ब्यास से मिलने वाला पानी का हिस्सा कम हो गया है। बीएसएल से कम डिस्चार्ज देहर पावर हाउस में टेक्निकल दिक्कतों से जुड़ा है, जो डायवर्जन सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है। हरियाणा को पानी की कमी का डर है क्योंकि ब्यास-सतलज लिंक प्रोजेक्ट में देहर टर्बाइन की समस्या आ रही है।

राज्य ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ब्यास के पानी को सतलुज सिस्टम में बिना रुकावट के डायवर्जन करना अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हरियाणा ने नदी के पानी में अपने हिस्से को लेकर नई चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उसे चल रहे साइकिल में ब्यास नदी से अपना सही कोटा नहीं मिल सकता है। देहर प्रोजेक्ट में छह में से सिर्फ दो टर्बाइन अभी चालू हैं, जिससे ब्यास बेसिन से सतलुज में पानी का ट्रांसफर काफी कम हो गया है।

बीबीएमबी ने इस समस्या के लिए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़िम्मेदार ठहराया है और कहा है कि देहर पावर हाउस चार दशक से ज़्यादा पुराना है, जिसको तुरंत ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। अधिकारियों ने कहा कि बीबीएमबी ने टर्बाइनों के रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए पहले ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को हायर कर लिया है। रिपेयर और ओवरहॉल प्रोसेस में समय लगने की उम्मीद है। बीबीएमबी के एक अधिकारी ने बताया कि भाखड़ा डैम में सभी पार्टनर राज्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफी पानी मौजूद है।

हरियाणा को पानी की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मौजूद रिसोर्स के अंदर स्थिति को मैनेज किया जा रहा है। पिछले साल पंजाब के साथ कई दिनों तक बीबीएमबी के पानी को लेकर चले विवाद के मद्देनजर हरियाणा के अधिकारियों ने बताया है कि अगर राज्यों के बीच मतभेद होते हैं, तो सिर्फ भाखड़ा में जमा पानी पर निर्भर रहना काफी नहीं हो सकता है।

गंगा नहर से मिल सकेगा गुरुग्राम- फरीदाबाद को पीने का पानी

नई दिल्ली| गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों के लिए गंगा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा की नायब सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंचाई विभाग को नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए फिजिबिलिटी (व्यवहारिता) जांच करने के आदेश जारी किए हैं। जांच रिपोर्ट दो माह में तैयार होगी, अगर संभावना बनी तो मुख्यमंत्री इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे।

ततीमा मामलों के निपटान के लिए प्रदेशभर में चलेगा विशेष अभियान

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीएम का निर्देश

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| ततीमा मामलों के निपटान के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। काफी संख्या में ततीमा के मामले लंबित हैं। इससे अनावश्यक विवाद और न्यायालयीन प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। प्रशासनिक कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए आगे से कहीं भी अधिग्रहण के बाद जमीन का जितना टुकड़ा बच जाएगा, उसका तत्काल ततीमा काटने पर जोर दिया जाएगा यानी दस्तावेज को अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि अधिग्रहण के बाद कितनी बच गई। इससे उन्हें आगे बची जमीन की खरीद-बिक्री करने में आसानी होगी।

सिविल लाइंस के स्वतंत्रता सेनानी भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों से कहा कि ततीमा के लंबित मामलों को देखते हुए तत्काल समाधान के लिए एक विशेष मुहिम के तहत योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने पर जोर दें। देरी के कारण आमजन को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रेजांगला चौक की स्वच्छता व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेजांगला चौक तथा शहीद लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक का सुनियोजित तरीके से सुंदरीकरण किया जाए ताकि ये स्थान न केवल साफ-सुथरे दिखें, बल्कि शहर की सुंदरता को भी बढ़ाएं। साथ ही रेजांगला स्मारक का समुचित सुंदरीकरण, पुनर्रचना (रीडिजाइनिंग) और समग्र उन्नयन किया जाए, ताकि इसे और अधिक आकर्षक, गरिमापूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जा सके।

दौलताबाद गांव से आए एक शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उसके खेत तक जाने वाले करीब दो करम चौड़े रास्ते पर दो बिल्डर्स द्वारा अवैध कब्जा कर दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे उसका तथा अन्य ग्रामीणों का खेतों में आवागमन बाधित हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कब्जा हटवाकर रास्ते को मूल स्वरूप में बहाल किया जाए तथा संबंधित बिल्डर्स से दोनों ओर अतिरिक्त दो-दो फीट जगह भी खाली करवाई जाए, ताकि ग्रामीणों के लिए आवागमन सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित किया जा सके। सेक्टर-10 से आए आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि क्षेत्र में पुराना सीवरेज सिस्टम होने के कारण बार-बार ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

15 में से 11 परिवारों का किया निपटान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर के लिए आधुनिक और सक्षम सीवरेज सिस्टम का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए, ताकि स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। जब तक नया सिस्टम लागू नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था जैसे नियमित सफाई, पंपिंग और जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके और स्वच्छता बनी रहे। बैठक में 15 परिवाद रखे गए थे, उनमें से 11 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।

पार्क सरीन सोसाइटी में एक हफ्ते से पेयजल संकट

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ पेयजल सप्लाई प्रभावित होने की शिकायत सामने आने लगी है। सेक्टर-37डी स्थित बीपीटीपी पार्क सरीन सोसाइटी में पिछले एक सप्ताह से जीएमडीए की पाइपलाइन से कम पेयजल मिल रहा है। इससे टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। बीपीटीपी पार्क सरीन आरडब्ल्यूए के प्रधान संदीप शर्मा ने बताया कि पिछले सात दिन से पेयजल कम आ रहा है। पेयजल की कमी को दूर करने के लिए टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इस वजह से लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। टैंकर से मंगवाए जा रहे पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक है। उन्होंने जीएमडीए के अधिकारियों को शिकायत दी है। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने बताया कि पेयजल कम आने की शिकायत मिल चुकी है। जेई और एसडीओ से रिपोर्ट तलब की है। इनकी तरफ से बताया जाएगा कि पेयजल सप्लाई में क्या दिक्कत आ रही है और कैसे समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सोसाइटी निवासियों को पर्याप्त पानी दिया जाएगा।

'सफेद नंबर प्लेट वाली बाइकों पर रोक लगे'

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| हरियाणा ऑटो चालक संघ के बैनर तले गुरुवार सेक्टर-29 के लेजर वैली पार्क के सामने पार्किंग में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इसमें अवैध रूप से चल रही बाइकों पर तत्काल रोक लगाने, शेयरिंग, सीएनजी-लोडिंग ऑटो चालकों ने भाग लिया और समस्याओं को उठाया।

धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता महीपाल तंवर ने की। मुख्य वक्ता के रूप में अशोक कुमार ने ऑटो चालकों की समस्याओं को गंभीर उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हरियाणा ऑटो चालक संघ की मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करवाने का प्रयास किया जाएगा। धरने के दौरान चालकों ने एकजुटता दिखाते हुए 15 सूत्रीय मांगपत्र के माध्यम से अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से रखा और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। प्रदेश में अवैध रूप से चल रही सफेद प्लेट वाली बाइकों पर तुरंत रोक लगाई जाएं। सभी ऑटो चालकों का 10 लाख का बीमा सरकार द्वारा किया जाएं। ऑटो, टैक्सी सहित सभी ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएं।

न्यूज ब्रीफ

उत्तम सिंह गुरुग्राम के नए उपायुक्त बने

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव करते हुए बुधवार को 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। अब उत्तम सिंह नए जिला उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उत्तम सिंह इससे पहले करनाल के डीसी और करनाल स्मार्ट सिटी के सीईओ के पद पर तैनात थे। अपनी कार्यकुशलता और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में उनके अनुभव को देखते हुए, उन्हें गुरुग्राम जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। निवर्तमान डीसी अजय कुमार का भी तबादला कर दिया गया है। सरकार ने उनकी प्रशासनिक क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री हरियाणा का डिप्टी प्रिंसिपल नियुक्त किया है। अब वह मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं देंगे।

फर्जी दस्तावेज बनाने पर केस दर्ज

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| यातायात पुलिस ने नो एंट्री में प्रवेश का फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में एक वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज किया है। पिकअप चालक को एसपीआर पर ट्यूलिप चौक के समीप से पकड़ा है। उप निरीक्षक मनोज कुमार एसपीआर पर गश्त पर थे। इस दौरान एक पिकअप को आते हुए देखा। उसे रुकवाने पर नो एंट्री में प्रवेश के दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। पिकअप चालक सुनील ने फर्जी दस्तावेज दिखाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सुबह आठ बजे से दस बजे और शाम पांच बजे से रात नौ बजे तक व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित होता है।

बच्चों की वजह से पिता की जान बची

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| ऑटो चालक और उसके दो बच्चों के अपहरण मामले में डीएलएफ फेज-एक थाना पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मनमोहन और उसका पिता नत्थू लाल ऑटो चालक मनोज का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने वाले थे। चार अप्रैल रात आठ बजे मनोज का सिकंदरपुर पहाड़ी हनुमान मंदिर के पास से अपहरण करने के लिए पहुंचे तब ऑटो में उसके दोनों बच्चे भी थे। ऐसे में मजबूरन आरोपियों ने दोनों बच्चों और मनोज का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता बच्चों के कारण मनोज की हत्या नहीं कर सके।

शहर में जुलाई से सौ ई-बसें चलाई जाएंगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| शहर में जुलाई से 100 ई-बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। इसको लेकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने पीएमआई इलेक्ट्रो मोबीलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ठेका स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। 55 रुपये 47 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बस संचालन की एवज में इस कंपनी को गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की तरफ से भुगतान किया जाएगा। मौजूदा समय में गुरुग्राम में 150 सीएनजी बस हैं। करीब आठ साल पुरानी बस होने की वजह से आए दिन इसमें खराबी आती रहती है। रोजाना 15 से 20 बस बीच रास्ते में दम तोड़ रही है।

जिले में जनगणना 16 से शुरू होगी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| डीसी अजय कुमार ने कहा कि जनगणना-2027 को सफल बनाने के लिए आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की सुविधा की जानकारी गांव-गांव और वार्ड स्तर तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकें। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से स्व-गणना के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक पंजीकरण कर अपनी जानकारी स्वयं भर सकेंगे। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित होगी। जानकारी जमा करने के बाद नागरिकों को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से एक यूनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी मिलेगी, जिसके बाद गणना कर्मी मौके पर पहुंचकर केवल सत्यापन करेंगे।

सौर ऊर्जा से तलाशेंगे रैपिड मेट्रो संचालन की संभावना

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| सौर ऊर्जा से रैपिड मेट्रो के संचालन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस सिलसिले में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल जनवरी माह तक रैपिड मेट्रो के संचालन पर 11.26 करोड़ रुपये का बिजली बिल आया था। अप्रैल, 2024 से लेकर जनवरी, 2025 तक बिजली बिल करीब 9.33 करोड़ रुपये था। बिजली बिल अधिक आने की स्थिति को देखते हुए रैपिड मेट्रो का संचालन सौर ऊर्जा से करने की संभावनाएं तलाशने का फैसला लिया है। रैपिड मेट्रो के सभी स्टेशन और डिपो को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। अप्रैल, 2025 से इस साल जनवरी माह तक रैपिड मेट्रो से आय 58.94 करोड़ थी। रैपिड मेट्रो गोल्फ कोर्स रोड पर दौड़ती है। 12.85 किमी लंबी इस मेट्रो में 11 स्टेशन हैं।

किफायती योजना वाली नई सोसाइटियों में कार पार्किंग अनिवार्य

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने किफायती आवास नीति (अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी) में बदलाव किया है। इस नीति के तहत नई विकसित होने वाली रिहायशी सोसाइटियों में कार पार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। पुरानी नीति में सिर्फ मोटरसाइकिल पार्किंग की सुविधा थी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने बदलाव को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। साल 2013 में इस नीति को बनाया गया था। नीति में सिर्फ मोटरसाइकिल पार्किंग की सुविधा थी। मौजूदा समय में इस नीति के तहत गुरुग्राम में विकसित करीब 100 रिहायशी सोसाइटियों में कार पार्किंग को लेकर विवाद बना हुआ है। यह विवाद बिल्डर और आरडब्ल्यूए या फ्लैट मालिकों के बीच हो रहा है। बिल्डर की रखरखाव एजेंसी की तरफ से नीति का हवाला देते हुए कार को सोसाइटी में प्रवेश नहीं देती है, जिसके बाद टकराव की स्थिति बन जाती है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष शिकायत पहुंचीं थी। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे कि इस नीति में बदलाव किए जाएं। कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसके बाद नीति में संशोधन किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस नीति के तहत फ्लैट की कीमतों में बढ़ोतरी की जानकारी निदेशक कार्यालय को दी है। गुरुग्राम में नई सोसाइटी में 5575 रुपये प्रति वर्ग फीट के रेट निर्धारित किए गए हैं। 1300 रुपये प्रति वर्ग फीट बालकनी की एवज में देनी होंगी। अधिकतम 100 वर्ग फीट की बालकनी होगी, जिसकी एवज में एक लाख 30 हजार रुपये देने होंगे।

ये हैं नए नियम : किफायती आवास नीति के तहत नई सोसाइटियों में एक फ्लैट के लिए एक कार पार्किंग अनिवार्य है। इसकी एवज में फ्लैट मालिक को फ्लैट की कुल कीमत की 10फीसदी राशि अतिरिक्त देनी होगी। निर्माणाधीन रिहायशी परियोजनाओं या हाल ही में नक्शे पास होने वाली सोसाइटियों में बिल्डर को दो तिहाई आवंटियों से सहमति लेनी अनिवार्य है। यह सुविधा कब्जा प्रमाणपत्र जारी हो चुके प्रोजेक्ट में लागू नहीं होगी।

गुरुग्राम में 10 हजार कर्मचारियों की हड़ताल, धारा 163 लागू : पुलिस कर्मियों से धक्का-मुक्की और तोड़फोड़, 6 कंपनियों में काम ठप; उपायुक्त बोले- सरकार ने वेतन बढ़ाया

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| हरियाणा के गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर की होंडा कंपनी के बाद अब आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को हड़ताल की। करीब दस हजार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी शर्तों की मांग को लेकर अपनी-अपनी कंपनी गेट के बाहर हड़ताल पर बैठ गए। इनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल रहीं। पुलिस ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया तो नोकझोंक हुई। धक्का-मुक्की कर पुलिसकर्मियों का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों का कहना था कि यह उनकी हक की लड़ाई है, जिसमें प्रबंधन और उनके बीच का मामला है। पुलिस को बीच में नहीं आना चाहिए और न ही प्रबंधन की तरफदारी करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया।

उधर, कर्मचारियों के हंगामे को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी। डीसी ने बताया कि पुलिस के इनपुट यह धारा-163 लागू की गई है। उधर, देर शाम सात बजे तक कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद कंपनियों में छुट्टी होने के बाद सभी कर्मचारी अपने घर चले गए। कहना था कि कल भी उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उधर, डीसी अजय कुमार ने देर शाम बयान जारी किया। कहा कि सरकार की तरफ से न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेजेज) की दरों में वृद्धि की गई है। यह एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। बताया कि अकुशल श्रमिकों का वेतन 11275 से बढ़ कर 15220, अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12430 से बढ़ कर 16780 रुपए और कुशल श्रमिकों का वेतन 13704 से बढ़ कर 18500 रुपए किया गया है। उच्च कुशल का वेतन 14389 से बढ़ कर 19425 रुपए हो जाएगा। यह बढ़ोतरी लगभग 35 प्रतिशत है।

हड़ताल पर क्यों गए कर्मचारी, यहां सिलसिलेवार ढंग से जानिए...

- **कंपनी मालिकों पर लंबे समय से शोषण करने का आरोप :** कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लंबे समय से शोषण का शिकार हैं। न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान, सुरक्षा और स्थायीकरण जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं। होंडा कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब सत्यम, मुंजाल शोवा, रिको और अन्य कंपनियों के कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर हैं। इससे मानेसर के पूरे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
- **हड़ताल की वजह से कंपनियों में काम ठप :** हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले कई साल से उनकी सैलरी में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आठ-आठ घंटे के मात्र 12 हजार रुपए दिए जाते है, उसमें भी नियम बताकर कई कटौतियां कर ली जाती हैं। गैस के दाम भी आसमान छू रहे है, ऐसे में कम सैलरी में परिवार को पालन-पोषण नहीं हो पा रहा है। हड़ताली कर्मचारियों प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल के चलते कंपनियों में कार्य पूरी तरह ठप हो चुका है, जिससे आईएमटी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।
- **कर्मचारी बोले- मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज होगाः** देर शाम सात बजे सभी कर्मचारी अपने घरों को लौट गए। उनका कहना था कि उनकी सैलरी में उचित वृद्धि की जाए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को सुरक्षा दी जाए। कर्मचारी नेता ने कहा कि प्रबंधन हमारी बात नहीं सुन रहा और पुलिस हमें दबाने की कोशिश कर रही है। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज होगा। कल भी हड़ताल रखी जा सकती है। स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिसकर्मियों के वीडियो बनाने को लेकर हड़ताली कर्मचारियों ने हंगामा किया।

उद्यमी बोले- ऑटोमोबाइल और गारमेंट्स सेक्टर को नुकसान

वहीं, उद्यमियों का कहना है कि यदि प्रबंधन और सरकार ने तुरंत संवाद नहीं किया तो यह आंदोलन अन्य फैक्ट्रियों में फैल सकता है, जिसका सीधा असर ऑटोमोबाइल्स सेक्टर की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। हालांकि, देर शाम डीसी अजय कुमार ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेजेज) की दरों में वृद्धि की गई है। यह एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। कर्मचारियों से अपील की कि वे संयम बरतें। उधर, देर रात तक संबंधित कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया था।

11 साल बाद जेल से बाहर आया रामपाल : मुस्कुराते हुए निकला, सोनीपत के सतलोक आश्रम पहुंचा, देखकर रोने लगीं महिला भक्त

हिसार (राजधानी चौपाल) | हरियाणा में हिसार के सतलोक आश्रम प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहा रामपाल शुक्रवार को 11 साल और 4 महीने 24 दिन बाद हिसार की सेंट्रल जेल-2 से निकला। परिवार के लोग उसे लेने के लिए जेल पहुंचे थे। जेल के गेट से रामपाल मुस्कुराता हुआ निकला। इस दौरान गेट पर तैनात एक पुलिस कर्मचारी ने रामपाल के सामने हाथ जोड़े। इसके बाद वह सफेद पर्दे लगी फॉर्च्यूनर में बैठकर निकल गया। 20 गाड़ियों के काफिले के साथ वह सोनीपत जिले के धनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंचा। यहां ग्रामीणों और समर्थकों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। आश्रम के अंदर जैसे ही रामपाल ने संबोधन शुरू किया तो कुछ महिला भक्त रोने लग गईं। 8 अप्रैल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल की जमानत मंजूर की थी। आज सुबह ही कोर्ट के आदेश पर रामपाल के वकीलों ने हत्या के दो मामलों में 5-5 लाख के बेल बॉन्ड जमा करवाए।

2014 में पुलिस और समर्थकों में टकराव हुआ : नवंबर 2014 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को एक केस में कोर्ट की अवमानना के एक मामले में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। 19 नवंबर 2014 में पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पहुंची। यहां पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच टकराव हुआ। इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई।

इसके बाद रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में हिसार कोर्ट ने रामपाल को दोषी ठहराया और हत्या सहित अन्य धाराओं में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में रामपाल पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था।

रामपाल की जेल से रिहाई का रास्ता ऐसे हुआ साफ...

- **सुनवाई में वकीलों के बीच जोरदार बहस:** सतलोक आश्रम मामले में आश्रम के मुखिया रामपाल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से 8 अप्रैल को बड़ी राहत मिली। लगभग 11 साल, 4 महीने और 22 दिन जेल में रहने के बाद कोर्ट ने रामपाल को नियमित जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और रामपाल के वकील के बीच ज़ोरदार बहस हुई।
- **सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया:** सरकारी वकील ने रामपाल को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि रामपाल पर बहुत गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके, गोलियां चलाईं और पेट्रोल बम भी फेंके। इससे

कई पुलिस वाले घायल हो गए। इसलिए, रामपाल को जमानत देना ठीक नहीं होगा।
- **रामपाल की लंबी कैद और उम्र का हवाला:** रामपाल के वकील ने कहा कि रामपाल 11 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। इस मामले में 900 से ज्यादा लोग आरोपी हैं, जिनमें से ज्यादातर को जमानत मिल चुकी है। कुल 425 गवाह हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 58 गवाहों की गवाही हो पाई है। ट्रायल जल्दी पूरा होने की उम्मीद नहीं है। वकील ने रामपाल की उम्र लगभग 78 साल बताते हुए, उनकी सेहत और मानवीय आधार पर भी जमानत देने की मांग की।
- **हाईकोर्ट ने दलील को सही माना:** दोनों तरफ के वकीलों की बातें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले पर विचार किया और कहा कि रामपाल लंबे समय से जेल में है और ट्रायल बहुत धीरे चल रहा है। कोर्ट ने यह भी माना कि बाकी आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इन सब बातों को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह मामला जमानत देने लायक है।
- **कोर्ट ने जमानत पर कड़ी शर्तें भी लगाईं:** कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रामपाल को नियमित जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन कुछ कड़ी शर्तें भी लगाईं। रामपाल भविष्य में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा और न ही ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होगा। अगर रामपाल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार उसकी जमानत रद्द करवा सकती है।

‘अक्षरम्-2026’ का भव्य आगाज: अनु मलिक के सुर से सजी श्याम

तुम आये तो आया मुझे याद-जीजेयु में आज चाँद निकला

हिसार (राजधानी चौपाल) | गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार (गुजविप्रौवि) में आज राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महाकुंभ ‘अक्षरम्-2026’ का धमाकेदार आगाज हुआ। इस ऐतिहासिक महोत्सव में प्रदर्शनी और स्वदेशी मेले का शुभारम्भ मुख्य अतिथि प्रसिद्ध संगीत निर्देशक अनु मलिक और व विशिष्ठ अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने किया। इसके साथ ही अनु मलिक ने अक्षरम् पर स्वरचित गाने का विमोचन किया। विश्व विख्यात संगीतकार अनु मलिक इस समारोह अपने गानों से धमाल मचाते हुए विद्यार्थियों से रचनात्मक पहलुओं पर सीधी चर्चा की। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुजविप्रौवि कैंपस की हरियाली ने मेरा मन मोह लिया है। प्रकृति के प्रति यह प्रेम प्रेरणादायक है।

हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर उन्हें राष्ट्र की संस्कृति और साहित्य से जोड़ना है: प्रो. नरसी राम बिश्नोई

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस आयोजन की भव्यता को देखते हुए हर साल विश्वविद्यालय साहित्य उत्सव का आयोजन करेगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर उन्हें राष्ट्र की संस्कृति और साहित्य से जोड़ना है। 'अक्षरम्-2026' इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जहां संवाद और कला के माध्यम से युवा पीढ़ी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

दरोली में अंडरग्राउंड खाल निर्माण पर उठे सवाल

3-4 महीनों में ही लीकेज, नक्के टूटे - किसानों में रोष, आरटीआई से खुलेंगे राज

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल) | गांव दरोली स्थित मोरी नंबर 21000 लेफ्ट पर नहरी विभाग द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड खाल का निर्माण कार्य अब विवादों में घिर गया है। निर्माण के महज 3-4 महीनों के भीतर ही खाल में कई जगहों पर लीकेज सामने आया है, जबकि इसके ढांचे (नक्के) भी टूटने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण खाल इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गया। इस स्थिति के चलते किसानों को सिंचाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है।

किसानों ने जताई नाराजगी : स्थानीय किसानों का कहना है कि खाल से पानी लगातार रिस रहा है, जिससे पानी की भारी बर्बादी हो रही है। कई किसानों ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के

खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आरटीआई से मांगी गई पूरी जानकारी : इस पूरे मामले को लेकर “राजधानी चौपाल” साप्ताहिक अखबार के संपादक राहुल हिंदुस्तानी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नहरी विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। आरटीआई में निर्माण की स्वीकृति, खर्च की गई राशि, ठेकेदार का विवरण, गुणवत्ता मानक, निरीक्षण रिपोर्ट, मेजरमेंट बुक (MB), बिल भुगतान और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई हैं।

जांच और सख्त कार्रवाई की मांग : आवेदन में मांग की गई है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही खाल की जल्द मरम्मत या पुनर्निर्माण कर किसानों को राहत देने की अपील की गई है।

30 दिनों में देना होगा जवाब : सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित विभाग को 30 दिनों के भीतर सभी मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

न्यूज ब्रीफ

गैस एजेंसी संचालकों की अहम बैठक 13 को करनाल में : सतेन्द्र सिंह

हिसार (राजधानी चौपाल) | आगामी 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे जिमखाना क्लब, करनाल में सभी गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर्स/एल.पी.

जी. वितरकों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में वर्तमान के ज्वलंत एवं प्रमुख मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी और भविष्य की रणनीति निर्धारित की जाएगी। यह जानकारी देते हुए ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (एन.डब्ल्यू.आर.) के प्रदेशाध्यक्ष सतेन्द्र सिंह ने बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की इस मीटिंग में हरियाणा प्रदेश व जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रमुख वितरक उपस्थित रहेंगे।

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का हिसार तक विस्तार करवाने के लिए रेल विभाग को पत्र भेजा

हिसार (राजधानी चौपाल) | रेसीडेंट्स वैलफेयर सोसायटी, सेक्टर 33 पार्ट-1 की बैठक प्रधान धर्मबीर पानु की अध्यक्षता में हुई जिसमें आपसी विचार विमर्श के बाद रेलगाड़ी संख्या 12801/12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का हिसार तक विस्तार करवाने की पुरजोर मांग की गई। बैठक में सचिव बलविन्द्र सिंह, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, सदस्य सुनील कड़वासरा, रामकुमार सांगवान, लक्ष्मीनारायण, बलबीर भुभंक, कोर सिंह नेहरा आदि उपस्थित रहे। बैठक में लिये गये फैसले के बाद रेल प्रबंधक, उरत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर को पत्र लिखकर कहा गया कि वर्तमान में उक्त गाड़ी जगन्नाथ पुरी से आनंद विहार टर्मिनल तक संचालित होती है, जहां यह गाड़ी प्रातः 3:50 बजे पहुंचती है तथा अगले दिन रात्रि 22:45 बजे पुनः प्रस्थान करती है। इस प्रकार लगभग 19 घंटे तक गाड़ी वहां रुकती है। प्रतिदिन हजारों यात्रियों की सुविधा के लिए इस गाड़ी का आसानी से हिसार तक विस्तार किया जा सकता है।

गांव बाड्या ब्राह्मणान के प्रमुख समाजसेवी श्रवण कुमार वर्मा पर हुआ जानलेवा हमला

हिसार (राजधानी चौपाल) | हिसार जिले के गांव बाड्या ब्राह्मणान के प्रमुख समाजसेवी श्रवण कुमार वर्मा ने मंगलवार को हिसार में एक प्रेस कांफ्रेंस कर 5 अप्रैल को उन पर हुए जानलेवा हमले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। श्रवण वर्मा ने आरोप लगाया कि कि गांव के ही इशू शर्मा उर्फ लीला फौजी उसके पिता राजिंदर शर्मा, चाचा रमेश शर्मा और चचेरे भाई चतुर्भुज शर्मा व राजू शर्मा ने उनके घर और फैक्ट्री पर हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने गेट तोडक़र अंदर घुसने की कोशिश की और ईंट-पत्थरों से हमला किया। उन्होंने कहा कि ये सभी आरोपी शातिर किस्म के हैं और पंडित रुलीराम शर्मा के परिवार से संबंध रखते हैं। वर्मा के अनुसार, इसी परिवार के रमेश शर्मा और रुलीराम शर्मा हत्या के मामले में कैद भी काट चुके हैं।

ओशो ध्यान उपवन में तीन दिवसीय मेडिटेशन कैंप

हिसार (राजधानी चौपाल) | सिरसा रोड स्थित ओशो ध्यान उपवन में 10 से 12 अप्रैल तक तीन दिवसीय मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सिरसा रोड स्थित ओशो ध्यान उपवन सज गया है। इस कैंप में पंजाब से विशेष रूप से आचार्य शेखर शिरकत करेंगे। वे ओशो की देशनाओं से रूबरू करवाते हुए ध्यान के विज्ञान पर प्रकाश डालेंगे। मेडिटेशन कैंप के आयोजक स्वामी संजय व मां सांची ने बताया कि मेडिटेशन कैंप 10 से 12 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से साधक बढ़-चढक़र हिस्सा लेंगे।

सालासर प्रकरण के विरोध में 14 को नागोरी गेट पर होगा 11 से 1 बजे हनुमान चालीसा का पाठ

21 सदस्यीय कमेटी 11 को एसपी व डीसी से मिलकर शिकायत देंगे

हिसार (राजधानी चौपाल) | सालासर धाम में 4 दिन पहले हिसार वासी संजय व उनके परिवारजनों से मारपीट कर बदसलूकी हुई थी, उसके खिलाफ 21 सदस्यों की जो कमेटी बनी थी, उसकी बैठक शुक्रवार को पंजाबी धर्मशाला में हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि कमेटी के सदस्य 11 अप्रैल को एसपी हिसार व डीसी हिसार से मिलकर उन्हें सालासर धाम ट्रस्ट को चलाने वाले परिवार और उनके बाउंसरों के खिलाफ शिकायत देंगे। यह जानकारी देते हुए कमेटी के सदस्य राजेन्द्र चुटानी ने बताया कि हिसार निवासी संजय के परिवार की महिलाओं से जो मारपीट की गई, उसके सम्बंध में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को लिखा जाएगा कि जो लोग प्राईवेट स्तर पर दुकानदारी चला रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकार ऐसी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले और उसको खुद चलाए तथा उससे होने वाली आमदनी को समाज की भलाई में प्रयोग किया जाए। साथ ही कमेटी ने सर्वसम्मति से यह भी फैसला लिया कि आने वाली 14 अप्रैल मंगलवार को नागोरी गेट पर प्रातः 11 से 1:00 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा जिसमें सालासर महाराज से यह दरख्वास्त की जाएगी कि सालासर धाम के संचालकों व मारपीट करने वालों को सद्बुद्धि दे ताकि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की घटिया हरकतें भविष्य में न हो। इस कार्यक्रम के बाद जल्द ही कमेटी की पुनः बैठक बुलाई जाएगी।

कमेटी के सदस्य राजेन्द्र चुटानी ने बताया कि भविष्य में होने वाली बैठक से पूर्व यदि प्रशासन ने सख्त कदम उठाकर संतोषजनक कार्यवाही न की तो एक दिन तय करके हिसार से सैंकड़ों गाड़ियों का काफिला जिन पर गुंडागर्दी के खिलाफ पोस्टर-बैनर लगे होंगे, सालासर धाम जाकर धरना दिया जाएगा और बालाजी महाराज के दर्शन किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राजस्थान और आसपास के बहुत से शहरों से कमेटी के सदस्यों के पास फोन आ रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी के खिलाफ विरोध जताने के लिये लोग सालासर धाम पहुंचते हैं तो हिसार से आने वाली सैंकड़ों गाड़ियों के काफिले को हजारों गाड़ियों में बदलने का काम करेंगे। राजेन्द्र चुटानी ने बताया कि आंदोलन की अगली रुपरेखा मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद होने वाली कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा किंतु यह तय है कि न्याय न मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। कमेटी सदस्यों ने शहर वासियों से अपील की है कि 14 अप्रैल को प्रातः 11 से 1:00 बजे तक सद्बुद्धि देने के लिए होने वाले हनुमान चालीसा के पाठ में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर एकता का परिचय दें।

शिवालिक स्कूल में हुआ पूर्व छात्र एवं पूर्व शिक्षक मिलन समारोह

170 पूर्व विद्यार्थियों को किया सम्मानित, 100 से अधिक सरकारी पदों पर तैनात

हिसार (राजधानी चौपाल) | बड़वाली ढाणी स्थित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिवालिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल में पूर्व छात्र एवं पूर्व शिक्षक मिलन समारोह का शानदार आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1989 से लेकर 2020 तक 170 पूर्व छात्र-छात्राओं का भव्य अभिनंदन किया गया। खास बात यह है कि इनमें से 100 से ज्यादा छात्र-छात्राएं देश के अलग-अलग राज्यों में सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। इसी तरह 25 से ज्यादा पूर्व शिक्षक अधिकारी रह चुके हैं। पूर्व छात्र-छात्राओं ने अपने विचार सांझा किये। कार्यक्रम के मुख्यातिथि रहे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य साधुराम जाखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों को अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। जयपुर से अनु, चंडीगढ़ से सुमन, राजेश-मसूरी, मोनिका-भिवानी, रवि-गुरुग्राम, ममता-सिरसा, प्रो. वर्षा सैनी-एचएयू, प्रदीप, मनोज वर्मा, कुलदीप इंजीनियर, संतोष, सुमन, ममता, उपासना-अहमदाबाद सहित अन्य शामिल रहे। स्कूल की वाईस प्रिंसीपल प्रीति सैनी, प्रबंधक गीता देवी, प्रो. ओमेन्द्र सांगवान, सुशीला, ज्ञानसिंह व आत्मप्रकाश मेहरा, रविन्द्र मोहन, विजेन्द्र सिंह, प्रिंसीपल भरत सिंह आदि मौजूद थे।

विधायक चंद्रप्रकाश ने गेहूं व सरसों की खरीद और उठान के बारे में किया विचार-विमर्श

विधायक ने जनता दरबार लगाकर सुनी हलकावासियों की समस्याएं

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल) | विधायक चंद्रप्रकाश ने आदमपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर हलकावासियों की समस्याएं सुनी और आदमपुर की अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने मंडी में गेहूं व सरसों की आवक व उठान प्रक्रिया का जायजा भी लिया। उन्होंने किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि सरकार को गेहूं व सरसों खरीद के समुचित प्रबंध करने के साथ ही किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए।

इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का किसानों को राहत देने का प्रयास होना चाहिए, इसकी अपेक्षा सख्त नियम बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। चंद्रप्रकाश ने कहा कि किसानों के लिए ट्रैक्टर की नंबर प्लेट की फोटो सहित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने की बात तर्कसंगत नहीं है। बदलते मौसम के बीच किसान जल्द से जल्द फसल की कटाई करके अनाज को मंडी में पहुंचाने की कवायद करता है। इस बीच अनाज खरीद के लिए सरकार द्वारा थोपे गए अतार्किक नियमों से किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

विधायक ने कहा कि सरकार की इन नीतियों के खिलाफ आदमपुर में किसान प्रदर्शन करके रोष भी जता चुके हैं। इन नीतियों से किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी व संबंधित लोग भी परेशान हैं। इसलिए सरकार को इन थोपे गए नियमों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनाज मंडियों में किसानों के पीने के पानी व फसलों को बारिश से बचाने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही फसल की तुरंत खरीद करके किसानों को भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत किसान बारदाने व अन्य सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं।

विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में हमेशा किसान, गरीब, मजदूर व पिछड़ा वर्ग सहित हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य किया है। भाजपा सरकार किसी की सुध लेने की अपेक्षा राजनीतिक रोटियां सेक रही है।

जीवीएस इंटरनेशनल स्कूल, दुबेटा के अव्वल छात्र सम्मानित

हिसार (राजधानी चौपाल) | जीवीएस इंटरनेशनल स्कूल, दुबेटा में गत वर्ष में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता रहे छात्रों को स्कूल प्रांगण में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया।

स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. प्रदीप सूरा ने बताया कि समारोह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं राजकीय स्कूल के सेवानिवृत प्रिंसीपल बी.एस. चाहर ने मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया तथा पिछले वर्ष स्कूल में आयोजित मेहंदी, डांस आदि प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों, अपनी कक्षाओं में वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले छात्रों के अलावा गत माह जीनियस करियर इंस्टिट्यूट, दुबेटा के शुभारंभ अवसर पर सहयोग देने वाले छात्रों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन सोनू पंघाल, डायरेक्टर संजय सिंह राव, प्रिंसिपल डॉ. प्रदीप सूरा सहित सभी अध्यापक भी मौजूद रहे।

आदमपुर थाना की बड़ी कार्रवाई: 7.7 ग्राम हेरोइन सहित दो नशा तस्कर गिरफ्तार

मंडी आदमपुर (राजधानी चौपाल) | नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना आदमपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो युवकों को हेरोइन (चिट्टा) के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हिसार के निर्देशानुसार की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ASI रोहताश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मंडी आदमपुर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर शिव कॉलोनी की ओर आने वाले हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारत ग्लास एल्युमिनियम दुकान के सामने, शिव कॉलोनी क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। कुछ ही देर बाद क्रांति चौक की तरफ से एक स्पलेंडर प्लस मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को काबू कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी : पकड़े गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है: सुरेंद्र नागर पुत्र ओमप्रकाश, निवासी गांव आदमपुर (हाल निवासी शिव कॉलोनी, मंडी आदमपुर) सुशील उर्फ छोटू पुत्र सीताराम, निवासी महलसरा बरामदगी और कार्रवाई तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 7.7 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 50 के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आरोपियों को उनके अधिकारों से अवगत कराया और नशीला पदार्थ जब्त कर लिया। थाना आदमपुर में आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है कि बरामद नशा कहां से लाया गया था और आरोपियों के संबंध किन बड़े तस्करों से जुड़े हुए हैं।

हाई कोर्ट के आदेश पर पंचकूला की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट का फैसला

एजेएल प्लॉट आवंटन केस में पूर्व सीएम हुड्डा आरोपमुक्त

पंचकूला/चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| पंचकूला स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोपमुक्त कर दिया। इस दौरान हुड्डा अपने वकीलों के साथ कोर्ट में मौजूद रहे। हालांकि, इसी मामले में नामजद रहे एजेएल के चेयरमैन व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा वर्ष 2020 में निधन हो चुका है।

दरअसल, एजेएल को पंचकूला में अखबार शुरू करने के लिए 1982 में जमीन आवंटित की गई। इसके बाद प्लॉट एचएसवीपी ने निर्माण न होने के कारण रिज्यूम कर लिया था। फिर 2005 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार वापस आने पर हुड्डा विभाग (अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) ने यह प्लॉट फिर से एजेएल को आवंटित कर दिया और बाद में जमीन के पुनः आवंटन का मामला मुद्दा बना। इसको लेकर काफी शिकायतें हुईं, जिसके बाद सीबीआई ने 27 जनवरी 2017 को मामले में केस दर्ज किया था। 1 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की, लेकिन हुड्डा हाई कोर्ट में चले गए। 2021 से 2025 तक स्टे रहा। सीबीआई का पूर्व सीएम हुड्डा पर आरोप था कि 64.93 करोड़ रुपए का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपए में पुराने रेट पर दे दिया।

भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले : इस मामले में लंबे समय से हाई कोर्ट से सुनवाई पर रोक लगी हुई थी, लेकिन ईडी की कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ रही थी। ईडी की कोर्ट में इस मामले में कुल 75 बार सुनवाई हुई, जिसमें शुक्रवार को आखिरी सुनवाई के दौरान एजेएल का चैप्टर बंद हो गया। इस मामले में फरवरी महीने में हाई कोर्ट ने हुड्डा को राहत देते हुए उन्हें मामले में डिस्चार्ज करने के आदेश जारी किए थे। हाई कोर्ट के आदेश मार्च में ईडी की कोर्ट में पहुंचे जिसमें 27 मार्च को सुनवाई हुई। उसी दिन कोर्ट ने हुड्डा को अगली सुनवाई पर पेश होने के आदेश दिए थे, जिसके चलते शुक्रवार को मामले में हुड्डा अपने वकीलों के साथ पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज कर आरोपमुक्त कर बरी करने के आदेश जारी किए।

मामला : 1982 से शुरू हुई थी प्लॉट की कहानी

24 अगस्त 1982 को पंचकूला सेक्टर-6 में 3360 वर्गमीटर का प्लॉट नंबर सी-17 तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल ने एजेएल प्रकाशन समूह के हिंदी अखबार नवजीवन को आवंटित किया था। कंपनी को छह माह में निर्माण शुरू करके दो वर्ष में काम पूरा करना था। वह 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1992 को एचएसवीपी ने आवंटन रद्द करके प्लॉट को वापस ले लिया। 18 अगस्त 1995 को नए आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें एजेएल कंपनी को आवेदन करने की छूट दी गई। 28 अगस्त 2005 को एचएसवीपी ने एजेएल को ही वर्ष 1982 की मूल दर पर प्लॉट आवंटित कर दिया था, जिसके बाद इस मामले में शिकायतों का दौर शुरू हुआ था।

क्रॉस वोटिंग को लेकर पांचों विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश, हो सकता है निलंबन

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस की अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट शनिवार को हाईकमान को भेज दी। यह पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास जाएगी। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट में इससे संबंधित फैक्ट भेजे गए हैं। साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जिसमें निलंबन भी शामिल है।

निलंबन होने पर विधायक कांग्रेस के तो बने रहेंगे, लेकिन उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर रखा जाएगा। हाईकमान फैसला 2028 में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव का देखकर लेगा। बताया जा रहा है कि एक-दो दिन में हाईकमान अपना फैसला जारी कर सकता है। अनुशासन समिति के नोटिस का 3 विधायकों ने ही लिखित जवाब दिया है। इनमें से दो ने समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने बयान भी दर्ज कराए।

कांग्रेस की कार्रवाई पर भाजपा की नजर : विधायक मोहम्मद इसराइल ने क्रॉस वोटिंग स्वीकार कर ली थी। उनके कार्यक्रमों में भाजपा सरकार के मंत्री भी दिखाई दिए। मोहम्मद इलियास भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर चुके हैं। बाकी तीनों विधायकों ने भी पार्टी में कलह पर खुलकर बोला है। ऐसे में भाजपा की कांग्रेस की कार्रवाई को लेकर चल रही प्रक्रिया पर नजर है, ताकि वह अगला कदम बढ़ा सके। शैली चौधरी तो कह चुकी हैं कि अगर पार्टी कार्रवाई करती है तो वे जनता के बीच जाएंगी।

मैं विधानसभा में घेरता हूं तो वॉकआउट कर जाते हैं कांग्रेसी व बाहर झूठ फैलाते हैं: नायब

सीएम ने हुड्डा, बीरेंद्र का नाम लिए बिना कहा- बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जींद का शोषण किया

जींद (राजधानी चौपाल)| सीएम नायब सैनी ने बांगर की धरती जींद में रैली में कांग्रेस समेत विपक्ष को खूब कोसा। कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विधानसभा में कांग्रेस के लोगों को जब मैं घेरता हूं तो वे वाकआउट कर जाते हैं और बाहर झूठ फैलाते हैं। जींद को लंबे समय तक विपक्ष ने नजर अंदाज किया, सिर्फ वोट की फसल विपक्ष एक ही एजेंडा घाट काटा और पक्ष का करो। इस क्षेत्र के लोगों के साथ उन्होंने हमेशा झूठे वायदे किए, विकास के बजाय यहां पिछड़ापन रखा।

रविवार को जींद में विधायक डॉ. कृष्ण मिढ़ा द्वारा आयोजित रैली में भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह ने कहा कि जींद की यह भूमि परिश्रम और प्रगति का संगम है। यह हरियाणा की वह धड़कन है, जहां जब किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है तो देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। सीएम ने कहा कि वे पूरे हरियाणा के किसानों के लिए जींद से ऐलान करते हैं कि मंडियों में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। किसान की फसल का एक-एक दाना सरकार एमएसपी पर खरीदेगी।

सीएम ने कहा कि देश में कोई भी आपदा आती है तो पीएम मोदी लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कि वैश्विक संकट में भी विपक्षी कांग्रेस के लोग राजनीति करते हैं। अब ईरान-इजराइल युद्ध के चलते पीएम मोदी ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी है। कांग्रेस के लोगों का कहना चाहता हूं कि हरियाणा में एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग कौन से चश्मा से देखते हैं, पता नहीं चलता।

झूठे वादे करके आपके वोटों की फसल तो दो-दो और तीन-तीन पीढ़ियों तक काटी गई

सीएम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जींद को लम्बे समय से नजर अंदाज किया गया। झूठे वायदे कर आपके वोटों की फसल तो दो-दो-तीन-तीन पीढ़ियों तक काटी गई, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस नेता हुड्डा और बीरेंद्र सिंह समेत विपक्ष का नाम लिए बगैर परिवारवाद की दलदल में फंसे लोग आपके बच्चों के भविष्य को लेकर संजीदा नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित किया है, हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है।

महम में 202.77 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास

महम (रोहतक) महम के राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में रविवार को आयोजित विकास रैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने 202 करोड़ 77 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट में सुंदरपुर में स्कूल भवन निर्माण, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना, भिवानी सब ब्रांच को सुदृढ़ करना व टाउन पार्क का नवीनीकरण समेत कई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने महम के ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरे का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां लिए गए फैसलों ने हमेशा समाज को नई दिशा दी है।

अग्निवीरों को ₹5 लाख तक का ब्याज बिना ऋण मिलेगा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा 'हरियाणा अग्निवीर नीति-2024' को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसे अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा। राव नरबीर ने कहा कि वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना लागू की गई थी, जिसके तहत भर्ती अग्निवीरों में से 25% अग्निवीरों को सेना द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार नियमित सेवाओं में शामिल किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत चार वर्षों की सेवा अवधि में अग्निवीरों द्वारा फंड में दिए गए 30% अंशदान व भारत सरकार के कॉर्पस फंड के योगदान को मिलाकर अग्निवीरों को लगभग 11.71 लाख का सेवा निधि पैकेज प्राप्त होगा। जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमिता के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा तीन वर्षों तक 5 लाख तक का ब्याज बिना ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।

न्यूज ब्रीफ

अनुबंध आधार पर भर्ती होंगे 195 विशेषज्ञ डाक्टर

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 195 पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। नूंह को छोड़कर अन्य जिलों के लिए चयनित विशेषज्ञ डाक्टरों में एमबीबीएस एवं डिप्लोमा की योग्यता वाले विशेषज्ञ डाक्टरों को एक लाख रुपये प्रति महीना तथा एमबीबीएस एवं एमडी/एमएस/डीएनबी योग्यता वाले विशेषज्ञ डाक्टरों को 1.50 लाख रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। विशेष तौर पर नूंह जिले के लिए चयनित विशेषज्ञ डाक्टरों में एमबीबीएस एवं डिप्लोमा की योग्यता वाले विशेषज्ञ डाक्टरों को 1.50 लाख रुपये प्रति महीना तथा एमबीबीएस एवं एमडी/एमएस/डीएनबी योग्यता वाले विशेषज्ञ डाक्टरों को दो लाख रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। आरती राव ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति से मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा मिलेगी और मौजूदा डाक्टरों पर कार्यभार भी कम होगा।

सभी न्यायालयों व राजस्व न्यायालयों में लागू होगी ई-समन प्रणाली

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सभी न्यायालयों तथा सभी राजस्व न्यायालयों में समन जारी करने और उनकी तामील के लिए ई-समन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले न्यायालयों और प्राधिकरणों को समन जारी करने और तामील के लिए ई-समन प्रणाली का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश जारी करें। साथ ही, राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों को भी इस प्रणाली को अपनाने और इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मामलों के निपटान में तेजी लाई जा सके।

15 मई को होंगे बार एसोसिएशन चुनाव, सदस्यता शुल्क ऑनलाइन जमा होगा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के चुनाव 15 मई को कराने का शेड्यूल जारी किया है। नामांकन से लेकर अंतिम सूची तक की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी करनी होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार सदस्यता शुल्क केवल डिजिटल माध्यम या बैंक ड्राफ्ट से ही जमा होगा, नकद भुगतान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बल्क पेमेंट भी अमान्य होगा। चेक से किए गए भुगतान 16 अप्रैल तक क्लियर होना जरूरी है, अन्यथा सदस्यता संदिग्ध मानी जाएगी। बार काउंसिल ने चेतावनी दी है कि समय पर चुनाव न कराने पर संबंधित एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी नियुक्त की जाएगी। चुनाव को लेकर सख्ती भी बढ़ाई गई है। उम्मीदवारों द्वारा पार्टियां, भीड़ जुटाना और पोस्टर-पंपलेट लगाना प्रतिबंधित रहेगा। केवल सीमित स्तर पर पेपरलेस ग्रीन कैंपेन की अनुमति दी गई है।

किसान विरोधी नियम बनाएगी तो होगा आंदोलनः टिकैत

भिवानी (राजधानी चौपाल)| भिवानी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आईएमटी जमीन छीनने का प्रोजेक्ट है। सरकार व बड़े उद्योगपतियों की नजर किसानों की भूमि पर है। इंडस्ट्री के नाम पर जमीन खरीदेंगे, फिर महंगे रेट में बेच देंगे। इस तरह के नियमों के खिलाफ पहले जिस तरह का आंदोलन हुआ था, जरूरत हुई तो उसी तरह का मूवमेंट फिर चलेगा और पूरे देश में बैठकें चल रही हैं। टिकैत रविवार को पूर्व सांसद जंगबीर सिंह के निधन पर उनके आवास पर पहुंचे थे। वहीं टिकैत ने कहा कि अनाज मंडियों में फसल बिक्री के लिए किसानों की बायोमेट्रिक व ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट की फोटो की लेने का नियम गलत है। किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार इस तरह के किसान विरोधी नियम बनाएंगी तो फिर से आंदोलन होगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए किसानों से उनकी अपील है कि वे अपनी जमीन न बेचें।

हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदेश कार्यालय के लिए डीजीपी से मांगी सुरक्षा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर धमाका होने के बाद हरियाणा कांग्रेस ने अपने कार्यालय पर सुरक्षा करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया एवं कार्यालय प्रभारी संजीव भारद्वाज ने हरियाणा डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि पंजाब भाजपा के चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित कार्यालय के बाहर बम धमाका हुआ है। हालांकि मामले की जांच चल रही है, लेकिन चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के राजनीति पार्टियों के कार्यालय है।

हरियाणा कांग्रेस का चंडीगढ़ में सेक्टर-9 में प्रदेश मुख्यालय है। यह सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित है। यहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इसी कार्यालय में ठहरते हैं।

प्रदेश के में भरे जाएंगे ग्रुप-डी के रिक्त पद

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा सरकार ने चौकीदार और सफाई कर्मचारी के पदों को छोड़कर बोर्डों, निगमों, वैधानिक निकायों व सरकारी नियंत्रण वाली अन्य संस्थाओं में ग्रुप-डी के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। इन पदों पर भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों व बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को अपने विभागों और संबद्ध संस्थाओं में ग्रुप-डी के रिक्त पदों का विवरण भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में 10 अप्रैल, 2026 तक आवश्यक जानकारी मुहैया कराएं।

अभय, अजय ने अलग-अलग मनाई चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि

प्रदेश भर में सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| चौधरी देवीलाल की 25वीं पुण्यतिथि सोमवार को हरियाणा समेत पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। प्रदेश भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर पूर्व उपप्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की समाधि संघर्ष स्थल पर आयोजित हुआ। इनेलो सुप्रीमो चौ. अभय सिंह चौटाला, राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. सम्पत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजराल, विधायक अदित्य देवीलाल, युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी कर्ण चौटाला, विधायक अर्जुन चौटाला ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

जन-जन के नायक थे चौ. देवीलालः अजय

चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर जजपा ने दिल्ली में संघर्ष स्थल व सभी जिलों में उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। जजपा सुप्रीमो डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार सुबह दिल्ली समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए।

अजय चौटाला ने कहा कि हर साल अनुयायी देवीलाल को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ते है। चौ. देवीलाल द्वारा करवाए गए जनहितैषी कार्यों से आज भी आमजन लाभान्वित हो रहे है, तभी वे जन-जन के नायक कहलाते हैं।

मुख्यमंत्री के काफिले को जर्जर सड़क पर लगे झटके, दो जेई किए निलंबित

करनाल में असंध-कोहंड रोड से निकले थे सीएम

करनाल (राजधानी चौपाल) | करनाल में असंध से कोहंड रोड पर सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में पीडब्ल्यूडी के असंध डिवीजन के दो जूनियर इंजीनियर (जेई) दिनेश कुमार और राजेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार असंध-कोहंड मार्ग लंबे समय से खराब हालत में है। कई सालों बाद अब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन सालवन गांव के पास सड़क का एक हिस्सा अधूरा छोड़ दिया गया था। इस कारण वहां से निकलने वाले वाहनों का संतुलन बिगड़ रहा है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार रात को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला असंध-कोहंड रोड से निकल रहा था। जब काफिला सालवन गांव के पास पहुंचा तो सड़क का अधूरा हिस्सा होने के कारण उनकी गाड़ी को जोरदार झटके लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की और लापरवाही पर नाराजगी जताई।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेई दिनेश कुमार और जेई राजेंद्र कुमार को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। इस कार्रवाई के बाद रविवार सुबह ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क के गड्ढों को भरवा दिया और अधूरे हिस्से को ठीक कराने का काम शुरू कर दिया। एसडीओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि दोनों जेई को सस्पेंड कर दिया गया है।

पंचकूला में शूटिंग रेंज के लिए बजट मंजूर, करनाल में सिविल डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हरियाणा निवास में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं और खरीद प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में 10 से अधिक विभागों की योजनाओं पर करीब 1,028 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई, जबकि बोलीदाताओं से नेगोसिएशन कर करीब 96 करोड़ रुपए की बचत भी की गई।

सरकार ने बिजली उपकरणों की खरीद, 'हर-हित' रिटेल प्रोजेक्ट के तहत 29 करोड़ की पोषण सामग्री, मेडिकल कॉलेजों में 5.78 करोड़ के एसएफएलएम सिस्टम, गुरुग्राम में स्टॉर्म वाटर डायवर्जन (6.60 करोड़) समेत कई योजनाओं को स्वीकृति दी। इसके अलावा करनाल में सिविल डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर (47.20 करोड़), पंचकूला में अटल पार्क (20 करोड़) व शूटिंग रेंज (109.80 करोड़), पानीपत में सीईटीपी (123.40 करोड़) और गुरुग्राम में पंपिंग स्टेशन (101 करोड़) जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें, कार्य तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूरे हों।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खर्च की राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।

समाधान शिविरों से नदारद रहे अफसरों पर कार्रवाई

चंडीगढ़| प्रदेश में समाधान शिविरों पर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। वैसे अधिकारी जो काम में लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम नायब सैनी ने गुरुवार को ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों से एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर प्रदेशभर में संचालित समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा की।

सफीदों रैली : विपक्ष का केवल एक एजेंडा, झूठ बोलो और जनता को गुमराह करोः नायब सैनी

सफीदों (राजधानी चौपाल) | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास न कोई स्पष्ट नीति है और न ही कोई विजन है। विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है- भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और जनता को गुमराह करो। जब सच्चा विकास होता है तो झूठ की राजनीति करने वालों को तकलीफ होती है। विपक्ष के नेताओं ने केवल सत्ता का सुख भोगा, परिवारवाद को बढ़ावा दिया और जनता को वादों के जाल में फंसाकर छोड़ दिया। मुख्यमंत्री शनिवार को सफीदों में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली को संबोधित कर रहे थे।

खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब तक सिर्फ झूठ बोलने का एजेंडा बनाए हुए हैं। प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची-खर्ची के नौकरी मिल रही हैं। आगजनी में हुए मृतकों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सफीदों में गत दिनों हुई आगजनी में मृतकों के परिजनों से उनके आवास पर जाकर मिले। सीएम ने पीड़ित परिवारों को ढाढस बंधाते हुए कहा कि ऐसी दुखद घटना किसी के साथ ना हो।

मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा और घायलों के इलाज का खर्चा सरकार वजन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा और दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा।

सीएम का अफसरों को निर्देश- बरसात से पहले ड्रेन, नहरों की सफाई का काम पूरा हो

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में बरसात से पहले सभी ड्रेन, नहरों व नालों की सफाई का काम पूरा किया जाए। विशेषकर आबादी क्षेत्र में ड्रेन एवं नहरों के साथ मजबूत बर्म बनाएं जाएं और कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। वे सिंचाई, जनस्वास्थ्य एवं स्थानीय निकायों विभाग के अधिकारियों के साथ ड्रेन, नहरें एवं नालों की सफाई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम ने कहा शहरीकरण बढ़ने से जल निकासी बाधित हो रही है, जिससे जलभराव की स्थिति बनती है। इसे रोकने के लिए नईं जल निकासी परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएं, इसमें कोई लापरवाही न बरतें। सीएम ने घग्गर, मारकंडा, टांगरी नदियों की सफाई, तटबंधों को मजबूत करने व कुरुक्षेत्र में चीका के पास सरस्वती नदी के बहाव को सीधा करने के निर्देश दिए। बावल क्षेत्र में औद्योगिक पानी की निकासी के लिए भी योजना तैयार होगी। उन्होंने कमजोर तटबंधों को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके किनारों पर पौधारोपण करने को कहा। जानकारी के अनसार, प्रदेश में 825 ड्रेन-नालों में से 713 पर काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष जून तक पूरा होगा।

संपादकीय...

सुनहरी फसल पर कुदरत का कहर, किसान की आंखों में आंसू

राम-राम भाइयों! अप्रैल का यह महीना हरियाणा के किसान के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। चारों तरफ सुनहरी गेहूं की फसलें लहराती थीं और किसान बैसाखी पर ढोल की थाप के साथ अपनी मेहनत को घर लाने की तैयारी करता था। लेकिन इस साल नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस समय मंडियों में रौनक होनी चाहिए थी और गांवों में कंबाइन मशीनों का शोर होना चाहिए था, उस समय आसमान से आफत बरस रही है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी ने अन्नदाता के सपनों को खेत की मिट्टी में मिला दिया है।

इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही मौसम ने ऐसे तेवर दिखाए हैं कि हर कोई हैरान है। तेज आंधी और तूफान ने खड़ी फसल को बिछा दिया है। गेहूं की वह बालियां जो भारी होकर कटाई के इंतजार में झुक रही थीं, अब ओलों की मार से जमीन पर लोट गई हैं। किसान देख रहा है कि उसकी छह महीने की मेहनत और पसीना पानी में बह रहा है। बारिश के कारण गेहूं का दाना काला पड़ने लगा है, जिससे न केवल वजन कम होगा बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ेगा।

किसान केवल अनाज ही नहीं उपजाता, वह अपने पशुओं के लिए साल भर के चारे यानी 'तुड़ी' का इंतजाम भी इसी समय करता है। बारिश और नमी के कारण गेहूं का फाना (पराली) गीला हो गया है। आंधी की वजह से जो गेहूं खेत में गिर गया है, उसकी तुड़ी बनाना अब नामुमकिन सा हो गया है। तुड़ी काली पड़ रही है और उसमें दुर्गंध आने लगी है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में चारे के दाम आसमान छुएंगे, जिससे दूध की कीमतों में भी भारी उछाल आएगा और आम आदमी की रसोई पर बोझ बढ़ेगा।

जो किसान अपनी फसल को जैसे-तैसे बचाकर मंडी तक ले आए हैं, उनकी मुसीबतें वहां भी खत्म नहीं हो रही हैं। मंडियों में उठान की गति धीमी है और खुले आसमान के नीचे रखा गेहूं अचानक होने वाली बारिश की भेंट चढ़ रहा है। तिरपालों की भारी कमी देखी जा रही है और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने से अनाज की बोरियां पानी में तैर रही हैं। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खुद बारिश में भीगते हुए उसे ढंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती उसकी लाचारी को और बढ़ा रही है। 'राजधानी चौपाल' के जरिए हम सरकार और प्रशासन तक यह आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि अब समय मीटिंगों का नहीं, बल्कि धरातल पर उतरने का है। गिरदावरी की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और नुकसान का उचित मुआवजा बिना किसी देरी के किसान के खाते में पहुंचना चाहिए। सरकारी खरीद के नियमों में ढील दी जानी चाहिए, ताकि नमी और चमक की कमी के नाम पर किसान का शोषण न हो। भाइयों, संकट बड़ा है और चुनौतियां भी अनेक हैं, लेकिन हरियाणा का किसान कभी हार नहीं मानता। बैसाखी का त्यौहार भले ही इस बार फीका पड़ गया हो, लेकिन हमें एक-दूसरे का हाथ थामकर खड़ा होना होगा।

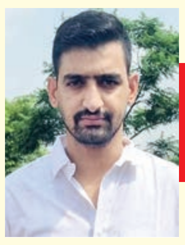

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

शिक्षा का बाजार-अभिभावकों की लाचारी

'एडमिशन' या 'किस्तों पर खरीदी गई ज़िंदगी'?

नमस्कार दोस्तों! राजधानी की हवाओं में इस समय केवल धूल और गर्मी ही नहीं है, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी भी है। यह बेचैनी है उन माता-पिता की, जिनके बच्चे अब नर्सरी या अगली बड़ी कक्षा में कदम रखने जा रहे हैं। शहर के हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर चर्चा का एक ही विषय है— 'भाई साहब, बच्चे का एडमिशन कराया या घर गिरवी रख दिया?'

आज की हमारी चौपाल इसी मुद्दे पर सजी है। शिक्षा, जिसे कभी दान और सेवा का पर्याय माना जाता था, आज वह राजधानी के गलियारों में एक 'कॉर्पोरेट डील' बन चुकी है। निजी स्कूलों ने शिक्षा के मंदिर को 'शॉपिंग मॉल' में तब्दील कर दिया है, जहाँ प्रवेश करते ही आपकी जेब पर पहला डाका 'एडमिशन फीस' के नाम पर डाला जाता है।

एडमिशन फीस का मायाजाल: एक बार की लूट या कानूनी डकैती?

सबसे पहले बात करते हैं उस 'प्रवेश शुल्क' यानी एडमिशन फीस की, जो किसी भी मध्यमवर्गीय परिवार की कमर तोड़ने के लिए काफी है। नियम कहते हैं कि एडमिशन फीस एक बार ली जानी चाहिए और वह भी तर्कसंगत हो, लेकिन हकीकत क्या है?

- **डोनेशन का नया नाम**: कई स्कूल सीधे तौर पर डोनेशन नहीं मांगते, लेकिन 'डेवलपमेंट फंड' या 'इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज' के नाम पर लाखों रुपये वसूल लेते हैं।
- **नॉन-रिफंडेबल का खेल**: आप एक बार फीस जमा कर दीजिए, और खुदा न खास्ता अगर आपको अगले महीने शहर छोड़ना पड़े या बच्चा स्कूल न जाना चाहे, तो वह मोटी रकम भूल जाइए। स्कूल के रजिस्टर में 'नो रिफंड' की स्याही बहुत गहरी होती है।

जागने का वक्त आ गया है....

साथियों, शिक्षा व्यापार नहीं, संस्कार है। यदि आज हम चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ी केवल 'डिग्री' लेकर निकलेगी, ज्ञान और नैतिकता नहीं। राजधानी के हर नागरिक को यह समझना होगा कि आलीशान इमारतें और एसी कमरे बच्चे का भविष्य नहीं बनाते, बल्कि एक अच्छी नीयत और किफायती शिक्षा बनाती है। इस साल के एडमिशन सीजन में, दिखावे की दौड़ से बाहर निकलें और स्कूलों से उनकी सुविधाओं के बजाय उनकी जवाबदेही पर सवाल पूछें। क्योंकि जब तक हम ग्राहक बने रहेंगे, वे हमें लूटते रहेंगे। जिस दिन हम जागरूक अभिभावक बन जाएंगे, उस दिन शिक्षा फिर से 'सरस्वती का मंदिर' बन जाएगी।

आज की चौपाल में इतना ही! सोचिएगा जरूर...

निजी प्रकाशकों की पुस्तकें: 'कमीशन' का काला खेल

शिक्षा के बाजारीकरण का सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आता है जब स्कूल अपनी 'बुक लिस्ट' जारी करते हैं। एनसीईआरटी (NCERT) की किताबें जो शायद 500-700 रुपये में पूरा सेट आ जाएं, उनकी जगह निजी प्रकाशकों की रंग-बिरंगी किताबें थोपी जाती हैं।

- **सेटिंग का साम्राज्य**: स्कूल का एक खास प्रकाशक के साथ 'टाई-अप' होता है। वह किताब केवल एक ही दुकान पर मिलेगी, और उस पर एक रुपये की भी छूट नहीं मिलेगी।
- **कीमतों में भारी अंतर**: जो व्याकरण या गणित की किताब बाजार में 200 रुपये की मिल सकती है, वही निजी प्रकाशक के ठप्पे के साथ 600-800 रुपये में बेची जाती है।
- **एकाधिकार**: कई बार तो किताबें और कॉपियां स्कूल के अंदर ही 'स्टॉल' लगाकर बेची जाती हैं। अगर आपने बाहर से खरीदी, तो टीचर कह देंगे कि "कवर का रंग थोड़ा अलग है, यह नहीं चलेगी।"

यूनिफॉर्म और स्टेशनरी: ब्रांडिंग की मार

बात सिर्फ किताबों तक नहीं रुकती। अब तो मोजे, बेल्ट, जूते और यहाँ तक कि स्कूल बैग पर भी स्कूल का लोगो होना अनिवार्य है।

- **महंगे कपड़े**: आम बाजार में 300 रुपये में मिलने वाली शर्ट, स्कूल के 'अधिकृत विक्रेता' के पास 800 रुपये में मिलती है।
- **हर साल नया फैशन**: कई स्कूल तो हर दो-तीन साल में अपनी ड्रेस का डिजाइन बदल देते हैं ताकि छोटा भाई बड़े भाई की पुरानी ड्रेस न पहन सके। यह पूरी तरह से एक 'इकोनॉमिक मॉडल' है जो अभिभावक की जेब खाली करने के लिए बनाया गया है।

प्रलोभनों की चमक-धमक: स्कूल है या फाइव स्टार होटल?

आजकल के निजी स्कूल पढ़ाई से ज्यादा अपने 'इंफ्रास्ट्रक्चर' का विज्ञापन करते हैं। राजधानी की सड़कों पर लगे बड़े-बड़े होर्डिंग्स देखिए:

- एसी क्लासरूम और विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल।
- स्मार्ट बोर्ड और रोबोटिक्स लैब।
- विदेशी दौरे और घुड़सवारी की सुविधा।
- साहब, बच्चे को मंगल ग्रह पर भेजना है या गणित सिखाना है? इन चमक-धमक वाले प्रलोभनों का असल मकसद केवल एक है— अभिभावक की मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाना। हर पिता चाहता है कि जो उसे नहीं मिला, वह उसके बच्चे को मिले। इसी 'इमोशनल ब्लैकमेलिंग' का फायदा उठाकर स्कूल अपनी फीस में सालाना 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं।

मध्यम वर्ग की बेबसी और सरकारी तंत्र की चुप्पी

राजधानी की चौपाल पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 'प्रशासन कहाँ है?' सरकारें हर साल नियम बनाती हैं, आदेश जारी करती हैं कि स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे या किताबों के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत ढाक के तीन पात है।

- **शिकायत का डर**: कोई भी माता-पिता स्कूल के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उन्हें डर रहता है कि कहीं स्कूल उनके बच्चे को टारगेट न करने लगे या उसे स्कूल से निकाल न दिया जाए।
- **वैकल्पिक शिक्षा का अभाव**: सरकारी स्कूलों की स्थिति (कुछ अपवादों को छोड़कर) अभी भी ऐसी नहीं है कि एक अच्छी कमाई करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को वहां भेजने का जोखिम उठाए। इसी मजबूरी का फायदा निजी स्कूल उठाते हैं।

समाधान की राह: क्या बदल सकता है मंजर?

चौपाल पर केवल दुखड़े नहीं रोए जाते, समाधान की भी बात होती है। अगर हमें इस 'शिक्षा माफिया' पर लगाम लगानी है, तो कुछ कड़े कदम उठाने होंगे:

- **कैपिंग सिस्टम**: सरकार को हर क्षेत्र के हिसाब से स्कूल फीस की एक 'अपर लिमिट' तय करनी चाहिए।
- **NCERT अनिवार्य हो**: निजी प्रकाशकों की किताबों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे या फिर उन्हें केवल संदर्भ पुस्तक के रूप में रखा जाए।
- **ऑडिट की पारदर्शिता**: हर निजी स्कूल का सालाना ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए ताकि पता चले कि जो करोड़ों रुपये वसूले जा रहे हैं, वे जा कहाँ रहे हैं।
- **अभिभावक संघ की मजबूती**: हर स्कूल में एक सक्रिय और स्वतंत्र 'पैरेंट्स-टीचर एसोसिएशन' होनी चाहिए, जो केवल स्कूल के सुर में सुर न मिलाए बल्कि सवाल भी पूछे।

लेखक : राहुल हिंदुस्तानी

युद्ध सात समंदर पार, पसीना किसान की माथे पर...

किराया बढ़ा, निवाला घटा : ट्रांसपोर्टेशन की मार और थाली से गायब होती सब्जियां

राम-राम भाइयों! आज की चौपाल किसी साधारण मुद्दे पर नहीं, बल्कि उस 'आर्थिक सुनामी' पर है जिसने हरियाणा के शांत गाँवों और धड़कते शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग कहते हैं कि राजनीति और युद्ध बड़े लोगों के खेल हैं, लेकिन जब अमेरिका की मिसाइलें चलती हैं, इजराइल के आयरन डोम गरजते हैं और ईरान की धमक सुनाई देती है, तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है।

आज की इस विशेष चौपाल में हम उस दर्द की परतें खोलेंगे, जो एक आम हरियाणवी महसूस कर रहा है। 'भाई साहब, जंग वहां हो रही है, पर पसीना यहाँ आ रहा है'—यही आज की कड़वी हकीकत है।

तेल का 'खेल' और हरियाणा की लाइफलाइन पर ब्रेक

हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसकी धमनियों में खून नहीं, बल्कि डीजल दौड़ता है। चाहे खेत में चलता ट्रैक्टर हो या दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दौड़ते ट्रक, सब कुछ तेल पर निर्भर है।

- **कच्चे तेल की आग** : खाड़ी देशों में अस्थिरता का मतलब है कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, ब्रेंट क्रूड की कीमतें रॉकेट बन जाती हैं। आज स्थिति यह है कि पेट्रोल-डीजल के दाम उस स्तर पर पहुँच गए हैं जहाँ एक आम नौकरीपेशा आदमी अपनी मोटरसाइकिल निकालने से पहले दस बार सोचता है।
- **खेती की लागत में भारी उछाल** : हरियाणा का किसान पहले ही खाद और बीजों की मार झेल रहा था, अब डीजल की महंगाई ने उसे 'बैकफुट' पर धकेल दिया है।
- **बुवाई और कटाई**: ट्रैक्टर चलाने का खर्चा प्रति एकड़ 500 से 800 तक बढ़ गया है।
- **सिंचाई का संकट**: जहाँ बिजली नहीं पहुँचती, वहां डीजल इंजन ही सहारा हैं। महंगे तेल का मतलब है महंगी सिंचाई-महंगी फसल।

रसोई गैस (LPG) का अकाल: चूल्हे की आग ठंडी पड़ी

युद्ध का सबसे पहला हमला रसोई पर होता है। भारत अपनी जरूरत की अधिकांश गैस खाड़ी देशों से आयात करता है।

- **सिलेंडर की 'सेंचुरी' और 'डबल सेंचुरी'** : वो दिन लद गए जब सिलेंडर के दाम बढ़ने पर विरोध होता था, अब तो लोग इस बात से डरते हैं कि सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरों ने सप्लाई चेन को तोड़ दिया है।
- **कालाबाजारी का डर**: जब भी युद्ध की खबर आती है, जमाखोर सक्रिय हो जाते हैं। हरियाणा के छोटे कस्बों में गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी कतारें इस बात का सबूत हैं कि लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं।
- **कमर्शियल गैस और मिड-डे मील** : केवल घरों की रसोई ही नहीं, स्कूलों में बच्चों का मिड-डे मील और हलवाइयों की भट्टियां भी इस महंगाई की चपेट में हैं। ढाबों पर रोटी के दाम 2 से बढ़कर 5 हो गए हैं, और इसका कारण केवल आटा नहीं, बल्कि उसे पकाने वाली 'महंगी आंच' है।

ऑटो हब गुड़गांव और फरीदाबाद का दम घुटता उद्योग

हरियाणा को देश का 'ऑटोमोबाइल हब' कहा जाता है। मारुति से लेकर हीरो मोटोकॉर्प तक, यहाँ बड़ी कंपनियों का जाल है। लेकिन युद्ध ने इस चमक को फीका कर दिया है।

- **कच्चे माल की कमी** : गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जे और चिप्स इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं। ईरान-इजराइल संकट के कारण समुद्री रास्ते असुरक्षित हो गए हैं। जहाज अब लंबा चक्कर लगाकर आ रहे हैं, जिससे 'फ्रेट चार्ज' (किराया) चार गुना बढ़ गया है।
- **एमएसएमई की कमर टूटी** : फरीदाबाद की छोटी फैक्ट्रियां जो बड़ी कंपनियों को नट-बोल्ट और छोटे पुर्जे सप्लाई करती हैं, वे बंद होने की कगार पर हैं। कच्चे माल के दाम बढ़ने और बिजली की किल्लत ने प्रोडक्शन को आधा कर दिया है। 'साहब, ऑर्डर तो हैं पर बनाने की लागत मुनाफे से ज्यादा है,' यह आज हर छोटे उद्यमी का रोना है।

बासमती का 'ब्लैकआउट': चावल निर्यातकों की चिंता

हरियाणा का बासमती चावल पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरता है, खासकर ईरान और इराक में। लेकिन जंग ने इस खुशबू को बारूद की गंध में बदल दिया है।

- **पेमेंट का संकट** : ईरान हमारा सबसे बड़ा बासमती खरीदार है। युद्ध और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग चैनल बंद हो जाते हैं। हरियाणा के राइस मिलर्स का करोड़ों रुपया ईरान में फंसा हुआ है।
- **अटका हुआ स्टॉक**: बंदरगाहों पर हजारों कंटेनर खड़े हैं। चावल खराब हो रहा है और निर्यातक ब्याज के बोझ तले दब रहे हैं।
- **मंडी में गिरते दाम** : जब निर्यात रुकता है, तो माल लोकल मंडियों में आता है। सप्लाई ज्यादा होने से किसान को अपनी फसल का वह दाम नहीं मिल पाता जिसका उसने सपना देखा था। यह हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक सीधा प्रहार है।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स: हर चीज पर 'युद्ध टैक्स'

हरियाणा उत्तर भारत का एक प्रमुख लॉजिस्टिक गेटवे है। यहाँ से ट्रक पंजाब, हिमाचल और जम्मू तक जाते हैं।

- **ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल जैसी स्थिति** : डीजल के दाम और टोल टैक्स में बढ़ोतरी ने ट्रक मालिकों को बेबस कर दिया है। किराया बढ़ने से फल, सब्जियां, दूध और राशन की कीमतें आसमान छू रही हैं।
- **आम आदमी की थाली**: टमाटर और प्याज के भाव युद्ध की खबरों के साथ ऊपर-नीचे होते हैं। परिवहन महंगा होने का मतलब है कि थाली से पोषण का गायब होना।

बिजली संकट: कोयला और गैस का खेल

हरियाणा की बिजली का एक हिस्सा गैस आधारित संयंत्रों से आता है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो स्टेट ग्रिड पर बोझ पड़ता है।

- **अघोषित कट**: गांवों में 8-10 घंटे की बिजली कटौती अब आम बात हो गई है। उद्योगों को बिजली देने के लिए घरेलू सप्लाई काटी जा रही है, जिससे इस भीषण गर्मी में आम आदमी का जीना मुहाल है।

शिक्षा और रोजगार: युवाओं के सपनों पर ग्रहण

हरियाणा का युवा बड़ी तादाद में पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाता है। खाड़ी देशों में और इजराइल जैसे देशों में कई हरियाणवी युवा निर्माण कार्यों और आईटी सेक्टर में लगे हैं।

- **वापसी का डर और वीजा संकट** : युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से युवाओं की वापसी की खबरें उनके परिवारों को डरा रही हैं। इजराइल में काम करने गए युवाओं के माता-पिता हर पल टीवी से चिपके रहते हैं।
- **महंगी उच्च शिक्षा**: डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने से उन छात्रों का बजट बिगड़ गया है जो विदेश में पढ़ रहे हैं। उनकी फीस अब 20% तक महंगी हो गई है।

समाधान की राह: क्या कर सकती है सरकार और हम?

चौपाल पर केवल समस्याओं का रोना नहीं रोया जाता, बल्कि समाधान भी तलाशे जाते हैं।

- **सौर ऊर्जा**: हमें अब अपनी निर्भरता खाड़ी के तेल से हटाकर सूरज की रोशनी पर लानी होगी। हरियाणा के हर खेत और घर पर सोलर पैनल ही इस 'ऊर्जा युद्ध' का जवाब हैं।
- **लोकल फॉर वोकल**: विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।
- **आपातकालीन कोष**: सरकार को एक ऐसा फंड बनाना चाहिए जो युद्ध जैसी स्थितियों में किसानों और छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण दे सके।

शांति ही एकमात्र रास्ता है...

भाइयों, खाड़ी के रेगिस्तान में जो बारूद बिछाया जा रहा है, उसकी लपटें हमारे हरियाणा के खेतों तक पहुँच चुकी हैं। यह युद्ध केवल मिसाइलों का नहीं, बल्कि हमारी जेबों, हमारी थालियों और हमारे बच्चों के भविष्य का है।

राजधानी की इस चौपाल से हम यही संदेश देते हैं कि जब तक दुनिया में शांति नहीं होगी, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं होगी। हमें जागरूक होना होगा, फिजूलखर्ची कम करनी होगी और अपनी मिट्टी की ताक़त को पहचानना होगा।

आज की चौपाल यहीं समाप्त होती है। अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक अपनी जेब और जज्बात दोनों को संभाल कर रखिये!

राम-राम हरियाणा!

ट्रम्प ने ईरान पर हमले 2 हफ्ते रोके : ईरान ने भी सीजफायर की पुष्टि की, होर्मुज खोलने पर राजी; नागरिकों से कहा- जीत का जश्न मनाएं

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल) | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले दो हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। ट्रम्प ने बताया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अपील के बाद लिया है। उन्होंने कहा- हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले दो हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होगा। ईरान ने भी सीजफायर की पुष्टि कर दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि आगे की बातचीत 11 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने दो हफ्ते के लिए होर्मुज खोलने की जानकारी दी और अपने नागरिकों से कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और जीत का जश्न पूरी ताकत से जारी रखें।

पाकिस्तानी PM ने अमेरिका-ईरान से बातचीत की जानकारी दी थी : इससे पहले शहबाज शरीफ ने X पर बताया था कि उन्होंने ट्रम्प से ईरान को दी गई डेडलाइन दो हफ्ते बढ़ाने की अपील की है। शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान से भी दो हफ्तों के लिए होर्मुज खोलने की अपील की है, ताकि इसे सद्भावना के संकेत के रूप में देखा जा सके।

सीजफायर के बावजूद इजराइल-ईरान के बीच हमले जारी : ईरान और अमेरिका के बीच घोषित 2 हफ्ते के सीजफायर के बावजूद जमीनी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइली वायुसेना ईरान में लगातार हमले कर रही है। वहीं, ईरान ने भी सीजफायर लागू होने के बाद इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की कई खेप दागी हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से लेबनान को भी सीजफायर में शामिल बताए जाने के बावजूद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोकने के संकेत नहीं दिए हैं।

ट्रम्प ने ईरान के विदेश मंत्री का सीजफायर बयान शेयर किया : ट्रम्प ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया है। इस बयान में 2 हफ्ते के सीजफायर समझौते और होर्मुज को खोलने की पुष्टि की गई है। अराघची ने अपने बयान में पाकिस्तान और उसके नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं, तो उसकी सशस्त्र सेनाएं भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी।

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सभी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन रोके : अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने सभी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिए हैं। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, हालांकि डिफेंसिव ऑपरेशन और सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे।

सीजफायर के बीच इजराइल और UAE में मिसाइल अलर्ट : ईरान और अमेरिका के बीच घोषित 2 हफ्ते के सीजफायर के बावजूद इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में बुधवार सुबह मिसाइल अलर्ट जारी किए गए। इससे संकेत मिलता है कि युद्धविराम के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मिसाइलों का निशाना क्या था या वे कहां से दागी गईं। दोनों देश युद्ध के दौरान पहले भी हमलों का सामना कर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार युद्ध में पक्ष अंतिम समय में हमले करते हैं, ताकि अपनी स्थिति मजबूत दिखा सकें।

व्हाइट हाउस बोला- ईरान के साथ आमने-सामने बातचीत पर विचार जारी : अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत की खबरों के बीच, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने एक बयान में कहा, "आमने-सामने की बातचीत पर विचार-विमर्श चल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस की तरफ से घोषणा किए जाने तक कुछ भी तय नहीं है।"

शहबाज शरीफ बोले- दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाई : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए सीजफायर समझौते को लेकर कहा कि यह समझौता लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। शरीफ ने दोनों देशों के नेतृत्व का आभार जताते हुए उनके प्रतिनिधिमंडलों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक में सभी विवादों के स्थायी समाधान पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने इस संकट के दौरान समझदारी और संतुलन दिखाया है और शांति की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा- हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता सफल होगी।

ईरान बोला- यह युद्ध अंत नहीं, तब तक लड़ेंगे जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होतीं

ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में बताया कि यह युद्ध का अंत नहीं है। ईरान युद्ध खत्म करने की शर्त तभी मानेगा जब 10-पॉइंट की योजना में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर उसके सभी डिटेल भी बातचीत में अंतिम रूप ले लिए जाएं। ईरान ने कहा- हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। अमेरिका से बातचीत के लिए हमने दो हफ्ते का समय दिया है। यह समय दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

ईरान ने कहा- अगर मैदान में दुश्मन का आत्मसमर्पण वार्ताओं में एक निर्णायक राजनीतिक उपलब्धि बनता है, तो हम इस ऐतिहासिक जीत का जश्न साथ मनाएंगे। नहीं तो हम मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर तब तक लड़ेंगे जब तक ईरानी जनता की सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, और दुश्मन की ओर से जरा सी भी गलती होने पर उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों तक होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही होगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था ईरानी सशस्त्र बलों के साथ समन्वय के जरिए लागू होगी और इसमें तकनीकी सीमाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। अराघची ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं, तो उसकी सेना भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगी।

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीजफायर समझौते की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह समझौता पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ है और इसे देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मोजतबा खामेनेई की मंजूरी मिली है। ईरान ने इस समझौते को अपनी जीत बताते हुए कहा है कि यह उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। बयान में कहा गया है कि अब स्थायी शांति समझौते के लिए आगे की बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी।

अमेरिका ने तकनीक चोरी होने के डर से अपने विमान जलाए

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान से एक बचाए गए अमेरिकी एयरमैन और कमांडो को निकालने वाले दो ट्रांसपोर्ट विमान वहीं फंस गए थे। इसके बाद अमेरिका को तीन नए विमान भेजने पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में अमेरिकी सेना ने उन फंसे हुए ट्रांसपोर्ट विमानों को उड़ा दिया, ताकि उनकी तकनीक ईरान के हाथ न लगे।

ईरान पर हमले के लिए कैसे माने थे ट्रम्प : नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस आकर प्लान बताया

वॉशिंगटन डीसी (राजधानी चौपाल) | तारीखः 11 फरवरी, जगहः व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुबह ही व्हाइट हाउस पहुंच चुके थे। वह कई महीनों से अमेरिका पर दबाव डाल रहे थे कि ईरान पर बड़ा हमला किया जाए। हालांकि इस बार की मुलाकात बेहद सीक्रेट थी। उन्हें बिना किसी औपचारिक स्वागत के सीधे अंदर ले जाया गया ताकि मीडिया को कुछ पता न चले। पहले कैबिनेट रूम में बातचीत हुई और फिर उन्हें व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ले जाया गया, जहां असली बैठक हुई। यह वही जगह है जहां अमेरिका युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले करता है, लेकिन आमतौर पर यहां विदेशी नेताओं को नहीं लाया जाता।

आमतौर पर जब कोई बड़ी मीटिंग होती है, तो ट्रम्प वह टेबल के सबसे आगे यानी 'हेड' वाली कुर्सी पर बैठते हैं। वहां से वह सबको देखते हैं और बैठक को लीड करते हैं। लेकिन इस मीटिंग में ट्रम्प टेबल के किनारे (साइड) पर जाकर बैठे, और उनका चेहरा दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ था। ट्रम्प-नेतन्याहू आमने-सामने थे। स्क्रीन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया और इजराइली सैन्य अधिकारी जुड़े हुए थे। इससे ऐसा माहौल बनाया गया जैसे नेतन्याहू युद्ध के समय अपने पूरे कमांड के साथ खड़े हैं।

इस बैठक में बहुत कम लोग शामिल थे ताकि कोई जानकारी बाहर न जाए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, सीआईए प्रमुख जॉन रैटक्लिफ, जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन, ट्रम्प के दामाद जैरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स भी वहां थीं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बैठक में नहीं थे, क्योंकि वे अजरबैजान में थे और बैठक अचानक तय हुई थी।

नेतन्याहू बोले- ईरान पर हमला करने का यह सही वक्त

नेतन्याहू ने एक घंटे का प्रेजेंटेशन दिया और ट्रम्प को समझाने की कोशिश की कि यह ईरान पर हमला करने का सबसे सही समय है। उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार कमजोर हो चुकी है और अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करें तो ईरान की सैन्य ताकत जल्दी खत्म की जा सकती है। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान का मिसाइल सिस्टम कुछ ही हफ्तों में तबाह किया जा सकता है और सरकार इतनी कमजोर हो जाएगी कि वह होर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं कर पाएगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान के अंदर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं और अगर इजराइल सीक्रेट तरीके से मदद करे तो ये प्रदर्शन सरकार गिराने तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इराक से कुर्द लड़ाके ईरान में घुसकर एक और मोर्चा खोल सकते हैं जिससे सरकार जल्दी गिर जाएगी। इस दौरान एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें उन संभावित नेताओं को दिखाया गया जो सरकार गिरने के बाद सत्ता संभाल सकते हैं। इसमें रजा पहलवी का नाम भी था, जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं और फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। नेतन्याहू ने बार-बार कहा कि अभी हमला जरूरी है, क्योंकि देर हुई तो ईरान मजबूत हो जाएगा। उनका कहना था कि कुछ न करने का खतरा, हमला करने से ज्यादा है।

ईरान को कमजोर समझने की भूल कर बैठे ट्रम्प

आने वाले दिनों में कई बैठकें हुईं। इन बैठकों में जनरल केन ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ बड़ा युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका के हथियार तेजी से खत्म हो सकते हैं। खास तौर पर मिसाइल इंटरसेप्टर पहले से ही कम हैं क्योंकि अमेरिका यूक्रेन और इजराइल की मदद करता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होगा और अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प को भरोसा था कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्हें लगा कि ईरान ज्यादा जवाब नहीं दे पाएगा, जैसा कि पहले जून में हुए हमलों के बाद देखा गया था।

तन्याहू की बातों में आ गए ट्रम्प

ट्रम्प इस पेशकश से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि यह प्लानिंग उन्हें सही लगती है। इससे नेतन्याहू को पता चल गया कि अमेरिका साथ आ सकता है। इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का काम इस प्लानिंग को समझना था। अगले दिन सिचुएशन रूम में सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें योजना को 4 हिस्सों में बांटा गया।

- खामेनेई और टॉप लीडरशिप को खत्म करना
- ईरान की सैन्य ताकत खत्म करना
- देश में विद्रोह करवाना
- सरकार बदलकर नई व्यवस्था लाना

खुफिया एजेंसियों ने कहा कि पहले दो मकसद हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी दो असलियत से दूर हैं। CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ ने इसे मजाक जैसा बताया और मार्को रूबियो ने इसे बेकार कहा। जब ट्रम्प बैठक में आए तो उन्हें यही रिपोर्ट दी गई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वापस आ चुके थे और उन्होंने इस योजना पर गहरी चिंता जताई। जनरल डैन केन ने भी कहा कि इजराइल अक्सर योजनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है क्योंकि उसे अमेरिका की मदद चाहिए होती है। इसके बाद ट्रम्प ने साफ कहा कि अगर सरकार बदलना संभव नहीं भी है तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता।

हमारी हड्डियां एक उम्र तक ही बनती हैं और मजबूत होती हैं। बाकी उम्र या तो इनकी घिसाई होती है या फिर उनकी मजबूती बनाए रखने की मरम्मत। कब बढ़ जाता है हड्डियों की कमजोरी का खतरा और कौन-सी जांच है जरूरी...

कमजोर हड्डियों का क्या है इलाज...

हफ्ते में 20 मिनट छाती और पीठ पर धूप लें...

अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अनुसार गलत खानपान व शारीरिक सक्रियता की कमी 35 से कम उम्र के लोगों में हड्डियों की कमजोरी व ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन रही है। कई सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में घूमते हैं, हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? क्या हमें भी हड्डियों की गहन जांच कराने की जरूरत है?

क्या है ऑस्टियोपोरोसिस

हड्डियों की कमजोरी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों का घनत्व इतना कम हो जाता है कि मामूली आघात लगने पर जैसे गिरने या फिसलने आदि से हड्डी टूटने की आशंका बढ़ जाती है। हमारी हड्डियां एक दिन में कमजोर नहीं होतीं। पर, कई बार लंबे समय तक इसके लक्षण प्रकट नहीं होते और उपचार में देरी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने की पूर्व स्थिति यानी हड्डियों के घनत्व के कम होने की प्रारंभिक स्थिति को ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है। यह बहुत गंभीर नहीं होती। इसके लक्षण हड्डियों में हल्का दर्द, मूवमेंट के दौरान हड्डियों में अकड़न, वजन उठाने में दिक्कत, थकान व हल्की चोट पर अधिक दर्द महसूस होने के रूप में दिखाई देते हैं। यही समस्या बढ़ कर ऑस्टियोपोरोसिस बन जाती है।

हड्डियों की कमजोरी के लक्षण

- **कद का कम होना** : रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रा की सिकुड़न से रीढ़ के ऊपरी भाग पर कूबड़(काइफोसिस)हो जाता है। इस कारण रीढ़ कुछ हद तक मुड़ जाती है। व्यक्ति झुककर चलता है। इसी तरह रीढ़ की कई हड्डियां बीच-बीच में टूटकर पिचक जाती हैं। इससे भी कद छोटा हो जाता है।
- **चलने में दिक्कत** : शरीर में खून व कैल्शियम कम होने पर शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेने लगता है। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं और चलने में दिक्कत होती है।
- **बार-बार फ्रैक्चर** : हड्डियां भुरभुराने के कारण मामूली चोट से फ्रैक्चर हो जाता है।
- **कमर दर्द** : रीढ़ की कमजोरी से कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है।

क्या है डेक्सा जांच

डॉक्टर ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज की प्रक्रिया डेक्सा स्कैन जांच की स्कोरिंग के अनुसार तय करते हैं। यही सबसे लोकप्रिय व सटीक जांच है। आमतौर पर टी स्कोर माइनस 2.5 से कम हो तो ऑस्टियोपोरोसिस मानते हैं। इसमें दो एक्स-रे बीम्स से हड्डियों की मोटाई मापते हैं। इसका उद्देश्य हड्डियों की स्थिति जानकर उनका क्षरण रोकना है।

- **क्या है इलाज** : शुरुआत में डॉक्टर खान-पान में सुधार व व्यायाम पर जोर देते हैं। मरीज की स्थिति के अनुसार कैल्शियम, विटामिन-डी और बिसफॉस्फोनेट्स की दवा भी दी जाती है। गंभीर स्थिति में उपचार लंबा चलता है। जीवनशैली व खान-पान के साथ डॉक्टर टेस्ट कराते हैं। कई बार पैराटाइड के इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसके अलावा रीढ़ में कूबड़ होने पर बैलून काइफोप्लास्टी नामक तकनीक का सहारा लिया जाता है।

मेनोपॉज और महिलाएं

आमतौर पर महिलाओं में 42 से लेकर 50 साल तक की उम्र के बीच रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) की प्रक्रिया घटित होती है। अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अनुसार मेनोपॉज की प्रक्रिया के दौरान और इसके बाद महिलाओं में इस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, जिसका हड्डियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। यही कारण है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में फ्रैक्चर की आशंका बढ़ जाती है। कई स्थितियों में डॉक्टर दवाओं के अलावा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं।

इनका रखें ध्यान

- **कैल्शियम उत्पादों को दें वरीयता**: हड्डियों के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी है। 20 से 50 साल के लोगों को प्रतिदिन लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए। जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है, उन्हें 1200 मिलीग्राम कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए। आमतौर पर शरीर एक समय में 500 मिलीग्राम कैल्शियम ही अवशोषित कर पाता है। दूध, दही, छाछ व पनीर खाएं। सोयाबीन, ब्रोकली, टोफू, अंजीर में भी कैल्शियम होता है। खानपान से पूर्ति न होने पर डॉक्टर कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं।
- **जरूरी है विटामिन डी** : विटामिन डी की कमी होने पर शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेने लगता है, जो कालांतर में हड्डियों को कमजोर बनाता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन 600 इंटरनेशनल यूनिट (आईयू) विटामिन डी लेना लाभप्रद है। रोज धूप में कुछ समय बिताना ही काफी पूर्ति कर देता है। दूध, पनीर, मशरूम, मछली खाएं। हफ्ते में तीन बार 20 मिनट छाती और पीठ पर धूप लें। कई बार डॉक्टर सप्लीमेंट्स व इंजेक्शन भी देते हैं।
- **प्रोटीन व फॉस्फोरस** : हारवर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन के अनुसार अपर्याप्त प्रोटीन का सेवन कैल्शियम अवशोषण को कम करता है। उम्र के अनुसार प्रोटीन की जरूरत अलग-अलग होती है, पर एक स्वस्थ वयस्क को अपने प्रति किलो वजन के अनुसार 0.8 से 1 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। डेयरी उत्पाद, फलियां, नट्स, अंडा, मीट व मछली आदि में यह पर्याप्त होता है। फॉस्फोरस व मैग्नीशियम की पूर्ति पर भी ध्यान दें। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, बीज, मेवे और मछली खाएं।
- **सही पॉश्चर** : गैजेट्स का इस्तेमाल करते समय सही पॉश्चर पर ध्यान दें।

तपती धूप और जलती दीवारों से राहत

बिना AC कैसे बनेगा आपका घर 'शीतल कुंज' - आर्किटेक्ट्स के अचूक देसी नुस्खे

जैसे-जैसे सूर्य देवता अपने रौद्र रूप की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को छूने के लिए बेताब है। कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते हमारे शहरों में अब घर 'आशियाना' कम और 'भट्ठी' ज्यादा महसूस होने लगे हैं। दोपहर होते ही छतें आग उगलने लगती हैं और दीवारें गर्म तवे जैसी हो जाती हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में पहला विचार एयर कंडीशनर (AC) का आता है, लेकिन क्या AC ही एकमात्र विकल्प है? बढ़ते बिजली बिल, ग्लोबल वार्मिंग और सेहत पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए अब दुनिया वापस अपनी जड़ों की ओर लौट रही है।

आज 'राजधानी चौपाल' के इस विशेष अंक में हम लखनऊ के प्रख्यात चार्टर्ड इंजीनियर व आर्किटेक्ट प्रमोद कुमार मौर्य और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. रोहित शर्मा के साथ हुई विस्तृत चर्चा के आधार पर आपके लिए लेकर आए हैं एक संपूर्ण 'कूलिंग गाइड'। जानिए कैसे आप अपने घर के तापमान को प्राकृतिक रूप से 5 से 10 डिग्री तक कम कर सकते हैं।

कंक्रीट की दीवारों का ताप और हमारा स्वास्थ्य

डॉ. रोहित शर्मा बताते हैं कि जब घर की दीवारें और छत गर्म होती हैं, तो वे 'थर्मल रेडिएशन' (तापीय विकिरण) छोड़ती हैं। यह गर्मी सीधे मानव शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, जिससे डिहाइड्रेशन, घबराहट और नींद न आने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। आर्किटेक्ट प्रमोद मौर्य के अनुसार, आधुनिक कंक्रीट (RCC) की छतों में हीट स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दिन भर की धूप को सोखने के बाद ये रात के 2 बजे तक गर्मी उगलती रहती हैं। यही कारण है कि रात में पंखा भी गर्म हवा देने लगता है।

क्रॉस वेंटिलेशन: घर के भीतर हवा का राजमार्ग

आर्किटेक्ट मौर्य का सबसे पहला और बुनियादी सुझाव 'क्रॉस वेंटिलेशन' है। वे इसे घर का "श्वसन तंत्र" कहते हैं। अक्सर लोग गर्मी के डर से खिड़की-दरवाजे हर समय बंद रखते हैं, जो गलत है।

विज्ञान क्या है? गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। यदि आपके कमरे में एक खिड़की से हवा आने और दूसरी ओर से निकलने का रास्ता नहीं होगा, तो वह गर्म हवा कमरे में ही 'ट्रैप' होकर तापमान बढ़ाती रहेगी।

- **देसी हैक**: सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम को सूर्यास्त के बाद घर के आमने-सामने के खिड़की-दरवाजे खोल दें। इससे 'स्टैक इफेक्ट' पैदा होगा और ठंडी हवा गर्म हवा को बाहर धकेल देगी।

'हीट ट्रैप' और ग्रीनहाउस इफेक्ट का समाधान

शहरों में फ्लैट संस्कृति बढ़ने से 'ग्लास विंडो' का चलन बढ़ा है। आर्किटेक्ट मौर्य आगाह करते हैं कि कांच की खिड़की सूरज की शॉर्ट-वेव रेडिएशन को अंदर आने देती है, लेकिन अंदर की लॉन्ग-वेव हीट को बाहर नहीं जाने देती। इसे ही 'ग्रीनहाउस इफेक्ट' कहते हैं।

- **बचाव के उपाय**: दोपहर के समय गहरे रंग के पर्दों के बजाय हल्के रंग के सूती पर्दों का प्रयोग करें। यदि संभव हो, तो खिड़की के बाहर बांस की चटाई (खस) लगाएं और उस पर पानी छिड़कें। यह एक प्राकृतिक डेजर्ट कूलर की तरह काम करेगा।

छतों के लिए 'कूल कोटिंग' और सफेद जादू

यदि आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं या आपका अपना स्वतंत्र मकान है, तो छत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है।

- **चूना और फेविकोल का नुस्खा**: यह सबसे सस्ता और प्राचीन देसी तरीका है। चूने में पानी और थोड़ा फेविकोल मिलाकर छत पर पेंट कर दें। सफेद रंग सूरज की किरणों को 80% तक रिफ्लेक्ट (परावर्तित) कर देता है।
- **सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट**: बाजार में अब कई ऐसे पेंट उपलब्ध हैं जो छत के तापमान को 15 डिग्री तक कम कर सकते हैं।

रूफ गार्डनिंग: छत पर हरियाली का कवच

मिट्टी और पौधे प्राकृतिक इंसुलेटर होते हैं। आर्किटेक्ट मौर्य सुझाव देते हैं कि अगर छत पर क्यारियां बनाई जाएं या गमले रखे जाएं, तो सीधे धूप कंक्रीट तक नहीं पहुंच पाती।

- **मिट्टी का कमाल**: छत पर बिछी 3-4 इंच की मिट्टी की परत गर्मी को नीचे के कमरे तक पहुंचने से रोकती है। यह उन लोगों के लिए रामबाण है जिनकी छत सीधे धूप के संपर्क में है।

इंडोर प्लांट्स: घर के भीतर ऑक्सीजन और शीतलता

पौधे केवल सजावट की वस्तु नहीं हैं, वे जीवित कूलिंग मशीनें हैं। 'ट्रांसपिरेशन' प्रक्रिया के दौरान पौधे अपनी पत्तियों से अतिरिक्त पानी वाष्पित करते हैं, जिससे आसपास की हवा ठंडी हो जाती है।

- **कौन से पौधे लगाएं**: स्नेक प्लांट, एरिका पाम, फर्न, और मनी प्लांट जैसे पौधे घर के भीतर की हवा को शुद्ध करने के साथ-साथ नमी बनाए रखते हैं। इन्हें खिड़कियों के पास रखने से अंदर आने वाली हवा ठंडी हो जाती है।

किचन और इलेक्ट्रॉनिक्स: घर के अंदर के गुप्त दुश्मन

डॉ. रोहित शर्मा के अनुसार, अक्सर हम बाहर की गर्मी पर ध्यान देते हैं, लेकिन घर के अंदर पैदा हो रही हीट को भूल जाते हैं।

- **गैस स्टोव और ओवन**: दोपहर के समय गैस स्टोव का कम से कम उपयोग करें। खाना बनाने के बाद एग्जॉस्ट फैन कम से कम 15 मिनट तक चालू रखें।
- **LED क्रांति**: यदि आपके घर में अभी भी पुराने पीले बल्ब (INCANDESCENT BULBS) हैं, तो उन्हें तुरंत बदलें। एक पीला बल्ब 90% ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद करता है। LED बल्ब ठंडे रहते हैं और बिजली भी बचाते हैं।

पंखे का सही उपयोग: एंटी-क्लॉकवाइज रोटेशन

आर्किटेक्ट मौर्य एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। गर्मी के मौसम में सीलिंग फैन की दिशा 'एंटी-क्लॉकवाइज' होनी चाहिए। क्यों? इस दिशा में घूमने पर पंखे की ब्लेड्स हवा को सीधे नीचे की ओर धकेलती हैं, जिससे पसीना जल्दी सूखता है और ठंडक का एहसास होता है।

यदि पंखा धीरे चल रहा है, तो उसका कंडेंसर बदलें, क्योंकि धीमी गति का पंखा सिर्फ मोटर की हीट पैदा करता है, हवा नहीं।

पारंपरिक बाटी को मिला नया अंदाज

इस बार चखें लच्छा बाटी का शाही स्वाद लच्छा पराठे की तरह खुलेंगी परतें

भारत की मिट्टी की खुशबू केवल खेतों में ही नहीं, बल्कि यहां की पारंपरिक रसोइयों में भी रची-बसी है। जब बात राजस्थानी और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की होती है, तो 'दाल-बाटी' का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बाटी के कई रूप हमने देखे हैं—कभी सादा, कभी मसाला बाटी तो कभी बाफला बाटी। लेकिन इस चिलचिलाती धूप और उत्सवों के मौसम में, राजधानी के भोजन प्रेमियों के बीच 'लच्छा बाटी' एक नए 'फूड ट्रेंड' के रूप में उभर रही है।

लच्छा बाटी, पारंपरिक बाटी का एक ऐसा आधुनिक और कलात्मक रूपांतरण है, जो अपने स्वाद और बनावट से बड़े-बड़े पकवानों को मात देता है। इसकी खासियत इसकी वे अनगिनत परतें हैं, जो लच्छा पराठे की तर्ज पर बनाई जाती हैं। 'राजधानी चौपाल' के आज के अंक में हम आपको बताएंगे इस शाही व्यंजन की पूरी कहानी और इसे बनाने की वह अनोखी तकनीक, जिसे जानकर आप भी अपने घर को किसी 'राजपूताना हवेली' के रसोईघर में तब्दील कर देंगे।

स्वाद और सेहत का मेल: क्यों खास है लच्छा बाटी?

साधारण बाटी अक्सर आटे के गोले के रूप में होती है, जो कभी-कभी अंदर से सख्त रह जाती है। लेकिन लच्छा बाटी की बनावट ऐसी होती है कि आंच इसकी हर परत तक पहुंचती है। इसमें धुली मूंग की दाल का मिश्रण मिलाया जाता है, जो इसे न केवल प्रोटीन से भरपूर बनाता है, बल्कि एक सोंधापन भी देता है। आर्किटेक्ट और भोजन विशेषज्ञों का मानना है कि खाने की बनावट उसके स्वाद को 40% तक बढ़ा देती है, और लच्छा बाटी इसी सिद्धांत पर काम करती है।

रसोई की सामग्री: सादगी में ही स्वाद है

किसके साथ परोसें?

राजधानी के मशहूर रसोइयों का सुझाव है कि लच्छा बाटी का असली मजा 'पंचमेल दाल' (पांच दालों का मिश्रण) और लहसुन की चटनी के साथ आता है। साथ में कटी हुई प्याज और नींबू इसके जायके को संपूर्णता प्रदान करते हैं। इस रविवार, आप भी अपनी रसोई में इस 'लच्छा बाटी' का प्रयोग करें। यह न केवल आपके परिवार के लिए एक नया अनुभव होगा, बल्कि पारंपरिक खान-पान के प्रति एक सम्मान भी होगा। याद रखें, अच्छा भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह स्मृतियां बनाता है।

इस शाही बाटी को बनाने के लिए आपको बाजार से किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं है। आपकी रसोई में उपलब्ध साधारण चीजें ही इसके जायके को असाधारण बनाएंगी:

- **मुख्य आधार**: 2 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी धुली मूंग की दाल।
- **मसालों का तड़का**: साबुत दरदरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक।
- **खुशबू का खजाना**: कसूरी मेथी, कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया।
- **नमी के लिए**: 3 चम्मच तेल (मोयन के रूप में)।
- **बनाने की कला**: दाल और आटे का संगम

लच्छा बाटी बनाने की प्रक्रिया किसी शिल्पकारी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है दाल को भिगोने से। धुली मूंग की दाल को 2 घंटे भिगोने के बाद जब उसे बारीक पीसा जाता है, तो वह एक मखमली पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट में जब कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च मिलती है, तो मसालों की एक जबरदस्त खुशबू उठती है।

आर्किटेक्ट ऑफ फूड (रसोइए) कहते हैं कि आटे का 'सख्त' होना इसकी सबसे बड़ी शर्त है। दाल के मसालेदार मिश्रण में जब गेहूं का आटा धीरे-धीरे मिलाया जाता है, तो यह बिना पानी के ही अपनी नमी से बंध जाता है। इसमें डाला गया तीन चम्मच तेल इसे वह 'खस्तापन' देता है, जो बाटी की असली पहचान है।

धागे की वह जादुई तकनीक: परतों का विज्ञान

इस बाटी का सबसे रोमांचक हिस्सा है इसके 'लच्छे' बनाना। सामान्यतः लोग इसे चाकू से काटते हैं, लेकिन पुराने उस्ताद यहां एक अनोखा नुस्खा अपनाते हैं।

- आटे की एक बड़ी रोटी बेलें और उस पर घी की एक हल्की परत लगाएं।
- इसका एक टाइट रोल बनाएं।
- अब यहां काम आता है 'धागा'। रोल के नीचे धागा रखकर उसे बीच से काटें। इससे परतों का मुंह नहीं दबता और वे पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं।
- कटे हुए हिस्से को ऊपर की तरफ रखते हुए जब आप इसे हल्का सा दबाते हैं, तो बाटी के ऊपर परतों का एक चक्र बन जाता है।

धीमी आंच और घी का अभिषेक

लच्छा बाटी को कभी भी तेज आंच पर नहीं सेंकना चाहिए। ओवन या तंदूर की धीमी आंच पर जब यह धीरे-धीरे सुनहरी होती है, तो इसकी एक-एक परत खिल उठती है। बाहर से सख्त और सुनहरी, और अंदर से मसालों की खुशबू लिए नरम—यही एक आदर्श लच्छा बाटी की पहचान है।

सेंकने के बाद, इसे सीधे देसी घी के कटोरे में डुबोया जाता है। घी इन परतों के भीतर तक जाकर इसे वह स्वाद देता है जिसे एक बार खाने के बाद जुबान भूल नहीं पाती।

प्रस्तुतिः - जायका डेस्क, राजधानी चौपाल

अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद कच्चा तेल 100 डॉलर के नीचे, 15 प्रतिशत सस्ता हुआ, 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| अमेरिका-ईरान जंग में 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) 15% सस्ता हुआ है। बुधवार को दाम करीब 15 डॉलर गिरकर 94.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह करीब 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। एक दिन पहले क्रूड ऑयल की कीमत 109.27 डॉलर प्रति बैरल थी। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले कच्चा तेल 73 डॉलर प्रति बैरल था। जंग के दौरान दाम बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए थे। तब से पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तेल सस्ता होने से अब यह आशंकाएं खत्म हो गई हैं।

सीजफायर के चलते होर्मुज खुलने की उम्मीद : अमेरिका-ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग पर 2 हफ्ते का ब्रेक लगा है। पाकिस्तान-चीन की मध्यस्थता के बाद दोनों देश सीजफायर पर सहमत हुए। समझौते के तहत अमेरिका, इजराइल और ईरान हमले रोकेंगे। ईरानी सेना की मदद से होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को तबाह करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से रास्ता नहीं मिला तो वह ईरान की पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे।

सीजफायर से ग्लोबल मार्केट उछले, डॉलर गिरा : युद्ध थमने की खबरों से ग्लोबल शेयर बाजारों में तेजी आई है। अमेरिका का S&P 500 फ्यूचर्स 2% और यूरोपीय बाजार 5% तक चढ़े। भारत के सेंसेक्स और निफ्टी भी करीब 4% चढ़े हैं। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से रूपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है।

RBI के मुताबिक, बुधवार के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 41 पैसे मजबूत होकर 92.55 पर पहुंच गया है। कल यह 92.96 पर बंद हुआ था।

जंग फिर शुरू हुई तो तेल के दाम दोबारा बढ़ेंगे : एनालिस्ट्स का कहना है कि अभी जो राहत दिख रही है, वह ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। आईजी के टोनी सिकामोर के अनुसार, यह एक अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन अभी कई बातें साफ नहीं हैं।

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर दो हफ्ते में पूरी तरह समझौता नहीं हुआ, तो कीमतें फिर से 100 डॉलर के ऊपर जा सकती हैं।

होर्मुज प्रभावित होने से तेल महंगा हुआ था :

जंग के बाद ईरान ने होर्मुज रूट लगभग बंद कर दिया था। दुनिया का करीब 20% तेल-गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होने से तेल, LPG, एल्युमीनियम, फर्टिलाइजर और प्लास्टिक महंगे हुए। ब्रिटेन-यूरोप में दवाओं और जरूरी चीजों की कमी का खतरा बढ़ा, क्योंकि शिपिंग खर्च कई गुना बढ़ गया था।

मार्च में क्रूड ऑयल 60% महंगा हुआ था : मार्च में कच्चे तेल में 60% उछाल आया था। यह 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद एक महीने में सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी।

फरवरी अंत में 72.48 डॉलर से बढ़कर मार्च में 120 डॉलर पार पहुंच गया था। इससे पहले सितंबर 1990 में सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमले के समय तेल की कीमतें एक महीने में 46% बढ़ी थीं। भारत के कुल तेल आयात का 51% खाड़ी देशों से आता है भारत कच्चे तेल के लिए सबसे ज्यादा पश्चिम एशिया पर निर्भर है। FY2025-26 के पहले 10 महीनों में कुल आयात में 51% हिस्सा इसी क्षेत्र का था। कीमत बढ़ने से आयात बिल तेजी से बढ़ रहा था।

कच्चा तेल सस्ता होने से भारत को क्या फायदे होंगे?

कच्चा तेल भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि हम करीब 85% तेल आयात करते हैं। तेल की कीमतें गिरने पर अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर राहत मिलती है।

1. पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे: कच्चा तेल सस्ता होने पर IOC, BPCL, HPCL जैसी कंपनियों के तेल की कीमत बढ़ाने की आशंका कम हो जाएगी। इससे ट्रांसपोर्ट लागत घटती है और आम आदमी के बजट पर असर पड़ता है।

2. महंगाई पर असर: डीजल के रेट न बढ़ने से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी नहीं। इससे फल, सब्जियां, अनाज और अन्य रोजमर्रा के खाने-पीने के सामानों के दाम नहीं बढ़ेंगे।

3. CAD में सुधार: कच्चा तेल सस्ता होने से इंपोर्ट बिल घटता है। विदेशी मुद्रा भंडार बचता है और करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD कम होता है।

4. रुपये को मजबूती: कच्चे तेल का बिल घटने से डॉलर की मांग कम होती है। इससे रुपया मजबूत होता है और आयात सस्ता होता है।

5. सब्सिडी बोझ कम: कच्चा तेल सस्ता होने से सरकार का सब्सिडी खर्च घटता है। बचा पैसा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर में लगा सकती है।

6. कॉर्पोरेट प्रॉफिट: तेल सस्ता होने से लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है। इससे शेयर बाजार पर पॉजिटिव असर पड़ता है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कच्चा तेल 10 डॉलर सस्ता होने पर करंट अकाउंट डेफिसिट में 9-10 बिलियन डॉलर की कमी और महंगाई में करीब 0.5% राहत मिल सकती है।

ट्रम्प फिर बोले-मेरा बस चले तो ईरानी तेल कब्जा लूं... इससे खूब पैसा कमाता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि अगर उनके पास मौका होता तो वे ईरान के तेल पर कब्जा कर लेते और खूब पैसा कमाते। ट्रम्प कुछ दिन पहले भी ईरानी तेल पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग आजादी चाहते हैं और वहां के हालात ऐसे हैं कि लोग बदलाव देखना चाहते हैं। हालांकि ट्रम्प ने यह भी माना कि अमेरिका के लोग अब युद्ध से थक चुके हैं और चाहते हैं कि सैनिकों को वापस घर बुलाया जाए। वहीं ईरान ने अमेरिका की तरफ से आए नए सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक, तेहरान ने कहा है कि वह अस्थायी युद्धविराम नहीं, बल्कि युद्ध का पूरी तरह और हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। ट्रम्प ने ईरान जंग पर सोमवार रात 10.30 बजे (भारतीय समय के मुताबिक) प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है।

सियासत • तार्किक विसंगति में 27.16 लाख नाम और कटे

बंगाल में मतदाताओं का गणित बदला; एसआईआर के बाद 91 लाख नाम कटे

कोलकाता (राजधानी चौपाल) | निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 90.83 लाख नाम हटे हैं। यह आंकड़ा राज्य के कुल मतदाताओं का 11.85% है। पिछले साल नवंबर में शुरू हुई प्रक्रिया के बाद 28 फरवरी को आई सूची में 63.66 लाख नाम हटे थे, तब 60.06 लाख वोटर्स 'विवेचनाधीन' श्रेणी में रखे गए थे।

जांच के बाद, इन 60.06 लाख में से 27.16 लाख और नाम हटाए गए हैं। वहीं, 32.68 लाख को पात्र मानकर सूची में शामिल किया गया है। करीब 22,163 लोगों के मामले में ई-हस्ताक्षर न होने से उनके नाम अभी सूची में दर्ज नहीं हैं। जिनके नाम कटे हैं उनकी मदद के लिए 19 न्यायाधिकरण बनने थे। हालांकि अभी शुरू नहीं हो सके। तार्किक विसंगति सूची में शामिल लोगों के दस्तावेज, नाम में गलती थी या माता-पिता के साथ उम्र के अंतर पर संदेह था।

60% नाम छह जिलों से हटे, 81% सीटें टीएमसी के पास

तार्किक विसंगति में हटाए गए नामों का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम बहुल व सीमावर्ती जिलों में है। इन 6 जिलों- मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नदिया, उत्तर व दक्षिण 24 परगना से करीब 60% नाम हटे हैं। इनमें से टॉप 5 जिलों में 115 सीटें हैं और इनमें से 93 (81%) सीटें अभी टीएमसी के पास हैं।

मतुआ बहुल इलाकों में भी नाम कटे... : राज्य में करीब 17% मतुआ समुदाय के लोग हैं, जो बांग्लादेश से आए हिंदू हैं। नॉर्थ 24 परगना में इनकी आबादी करीब 30% है। नदिया की कई सीटों पर प्रभाव है। इन जिलों में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं।

बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण की 152 सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि (सोमवार आधी रात) खत्म होने के साथ ही मतदाता सूची 'फ्रीज' कर दी गई। निर्वाचन आयोग के अनुसार, अब इस सूची में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही निर्भर करेगा, जिस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बाद सूची से मतुआ, राजवंशी और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम चुन-चुनकर हटाए गए हैं। हम ऐसे लोगों की कानूनी मदद करेंगे। इसका जवाब चुनाव में दिया जाएगा।

नंदीग्रामः जो नाम कटे उनमें 95% मुस्लिमः तार्किक विसंगति में इस चर्चित सीट पर करीब 2,826 नाम हटे हैं। इनमें करीब 2,700 यानी 95.5% मुस्लिम हैं। 2021 में इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करीब 2,000 वोट से हराया था।

1974 के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा संकट, दुनियाभर में इलेक्ट्रिक कुकिंग एलपीजी का विकल्प, ये गैस से 20 फीसदी तक सस्ती

मुंबई (राजधानी चौपाल)| ईरान युद्ध के बीच होर्मुज जल मार्ग बंद होने से दुनियाभर में रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत हो गई। इसी रास्ते से करीब 20% कच्चे तेल और एलपीजी का आयात-निर्यात होता है। अब भारत में सिलेंडर के लिए लाइनें लग रहीं, नेपाल में आधा सिलेंडर मिलने लगा, फिलीपींस में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ और बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी बंद हो गई। ऐसे में 20% सस्ती इलेक्ट्रिक कुकिंग एलपीजी का विकल्प बन रही है।

भारत में इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री अचानक 30 गुना तक बढ़ गई। केरल और महाराष्ट्र में बायोगैस प्लांट की मांग में उछाल आया और गुजरात के कई गांव सोलर कुकर अपनाने लगे। सिर्फ आम लोग ही नहीं, कैपजेमिनी जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने कैंटीन बायो-सीएनजी पर चलाना शुरू कर दिया। भारत में सरकार ने इंडक्शन कुकटॉप का उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर चर्चा शुरू कर दी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने इसे 1974 के बाद की सबसे बड़ी आपूर्ति बाधा कहा है।

इलेक्ट्रिक कुकिंग पर जोर की सबसे बड़ी वजह ये...

आईईए की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि होर्मुज बंद होने से रिफाइंड प्रोडक्ट एलपीजी की सप्लाई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इलेक्ट्रिक कुकिंग इसका बेहतर विकल्प हो सकता है, जो ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही एलपीजी से करीब 20% सस्ती थी। भारत जैसे देशों के लिए यह ज्यादा व्यवहारिक विकल्प है, जहां बिजली की पर्याप्त सप्लाई है।

20% दुनिया का तेल-एलपीजी होर्मुज से गुजरता था।

80% होर्मुज के रास्ते से तेल-गैस एशिया जाता था।

33 करोड़ भारत में एलपीजी कनेक्शन को नियमित सप्लाई की चुनौती।

इलेक्ट्रिक कुकिंग पर सरकारी इंसेंटिव

- **भारत :** बायो-सीएनजी, सोलर-स्टीम किचन, पीएनजी। सरकार का सोलर कुक टॉप का उत्पादन बढ़ाने पर जोर, तमिलनाडु में इंडक्शन सब्सिडी।
- **नेपाल:** इलेक्ट्रिक स्टोव बैकअप पर फोकस किया, भारत-नेपाल एलपीजी पाइपलाइन का प्रस्ताव।
- **श्रीलंका:** सोलर पैनल में निवेश बढ़ाया, सरकार ने सोलर कुक टॉप पर भी फोकस किया।
- **फिलीपींस:** इलेक्ट्रिक कुकर, ईवी पर इंसेंटिव की पहल, कोयले से बिजली बनाने पर जोर।
- **थाईलैंड/वियतनाम:** सरकार ने बायोफ्यूल पर 10% इंसेंटिव देने का ऐलान किया। इसके साथ ही कोयला से चलने वाले पावर प्लांट में निवेश भी बढ़ाया।

दुनिया के समक्ष एलपीजी के मोटे तौर पर 6 विकल्प

1. इंडक्शन कुकटॉप : भारत, श्रीलंका, फिलीपींस में बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। पर एक साथ लाखों घरों के स्विच से बिजली ग्रिड पर बोझ बढ़ रहा है।

2. सोलर कुकर : गुजरात के वडोदरा में सोलर-स्टीम किचन लाखों लोगों को खाना दे रहा। भारतीय बाजार में 1,000 से 5,000 रुपए में उपलब्ध है।

3. बायोगैस/बायो-सीएनजी : दिग्गज आईटी कंपनी कैपजेमिनी का बेंगलुरु कैंपस 100% बायोगैस पर चल रहा। इन्फोसिस के 8 कैंपस में रोज 9 टन फूड वेस्ट से गैस बनाई जा रही।

4. घरेलू डीआईवाई बायोगैस : 2,000-10,000 रुपए में घर पर सेटअप। सोशल मीडिया-यूट्यूब पर वायरल। किचन वेस्ट से रोजाना 1-2 घंटे खाना पकाने लायक गैस तैयार।

5. पाइप्ड गैस-पीएनजी : भारत ने 2030 तक 12 करोड़ घरों को पीएनजी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने सीएनजी-पीएनजी सप्लाई 100% बनाए रखने की घोषणा की।

6. पारंपरिक विकल्प : म्यांमार और अफ्रीका में लकड़ी-कोयले का इस्तेमाल फिर बढ़ा। भारत के गांवों में गोबर-गैस की वापसी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता- प्रदूषण बढ़ेगा।

थोरियम से बिजली बनाने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार; 400 साल की बिजली गारंटीः 200 से अधिक कंपनियों की मदद से बनाया स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश

- **ईंधन की बचतः** यह रिएक्टर इस्तेमाल किए गए ईंधन को फिर से रिसाइकिल कर ऊर्जा पैदा करता है।
- **सुरक्षाः** लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल, जो बिजली न होने पर भी रिएक्टर को खुद ही ठंडा रख सकता है।

कलपक्कम (राजधानी चौपाल)| भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वह कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने दुनिया के विकसित देशों को चौंका दिया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी-BHAVINI) का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) अब कमर्शियल उत्पादन के लिए तैयार है। इसे बनाने में 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई और निजी कंपनियों ने कलपुर्जे बनाए हैं। इस वजह से भारत पर किसी भी तरह के विदेशी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होगा।

रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है, जिसने इस जटिल तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर उतारा है। इसे किसी विदेशी मदद के बिना, पूरी तरह स्वदेशी इंजीनियरिंग से तैयार किया गया है। इससे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज-3 का रास्ता खुलेगा और थोरियम से परमाणु बिजली बनाना संभव होगा। परमाणु विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य रिएक्टरों की तुलना में 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' कहीं अधिक उन्नत होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जितना ईंधन (यूरेनियम) इस्तेमाल करता है, उससे कहीं ज्यादा पैदा करता है। इसीलिए इसे 'ब्रीडर' कहा जाता है। भारत के पास यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, लेकिन थोरियम का विशाल भंडार है। यह रिएक्टर भारत के 'तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम' के दूसरे चरण की शुरुआत है, जो भविष्य में थोरियम के इस्तेमाल का रास्ता खोलेगा। परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका, फ्रांस ने परमाणु रिएक्टर के एक ही डिजाइन- प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर (पीडब्ल्यूआर) को अपनाया। जर्मनी और ब्रिटेन की कोशिश नाकाम रही। भारत ने इस जटिल इंजीनियरिंग चुनौती को स्वीकार किया।

भारत में लगभग 9.63 लाख टन थोरियम का भंडार है। एक बार जब हम तीसरे चरण में पूरी तरह प्रवेश कर जाएंगे, तो ये भंडार भारत को अगले 400 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान करने में सक्षम होंगे। परमाणु वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोदकर के विजन का जिक्र करते हुए विशेषज्ञ बताते हैं कि हालांकि इस परियोजना में समय लगा, जो 'मेक इन इंडिया' की बड़ी मिसाल है। यह भारत की 'ऊर्जा संप्रभुता' का घोषणा-पत्र जैसा है।

RNI No. HARHIN/25/A3341, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी एवं संपादक राहुल कुमार द्वारा सूचना प्रिंटर्स 33एस मॉडल टाउन, हिसार से छपवाकर कार्यालय आदमपुर मंडी हिसार, (किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र हिसार न्यायालय होगा)।
संपादक : राहुल कुमार, फोन : 9306813001, e-mail : rajdhanichoupal@gmail.com, प्रकाशन स्थल : मकान संख्या : 114, शांति पार्क के पास, मंडी आदमपुर, हिसार (हरियाणा)